नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

परिवहन विशेष

www.newsparivahan.com

वर्ष 03, अंक 371, नई दिल्ली, बुधवार 11 मार्च 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

"शब्दों से नहीं,व्यवहार से पहचान बनती है। क्योंकि अच्छे शब्दकुछ समय के लिए याद रहते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहारजीवन भर याद रहता है।

03 चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल करें घरेलू उत्पाद ---खिल जाएगी आपकी त्वचा - शहनाज़ हुसैन

06 भारत में बुजुर्ग माता-पिता से संबंधित कानूनी मुद्दे

08 पंजाब सरकार ने अपने बजट में अपने सभी चुनावी वादे पूरे किए: जसकरण सिंह बंदेशा

परिवहन विशेष
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

India's First Leading English Transport Newspaper
parivahanvishesh

आरएनआई द्वारा दो भाषाओं में अनुमोदित, प्रकाशित समाचार पत्र "परिवहन विशेष" वार्षिक समारोह

दिनांक:- 29 मार्च , स्थान:- मावलंकर हाल, कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, समय:- 1 बजे से 5 बजे

परिवहन विशेष : हिन्दी एवं इंग्लिश भाषा दैनिक समाचार पत्र आपको अपने तृतीय वार्षिक समारोह में सम्मान पूर्वक शामिल होने के लिए निमंत्रित करता है
इस वर्ष का वार्षिक समारोह मुख्य रूप से "सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा" को समर्पित है।

मुख्य विशेषता :

1. विशेषज्ञों द्वारा जानने का प्रयास की भारत सरकार द्वारा देश में सख्त कानून लागू करने के बाद भी बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और सड़को पर उपलब्ध जाम का मुख्य कारण और उससे छुटकारा पाने के लिए क्या नीतियां अनिवार्य,
2. सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया, एनजीटी, वायु गुणवत्ता आयोग एवं सरकारों द्वारा नए नए दिशा निर्देशों, आदेशों के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण होने के स्थान पर बढ़ता जा रहा है उससे निजात पाने के लिए जाएंगे इस समारोह में विशेषज्ञों से उनके विचार
3. डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते भारत में बढ़ते साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है इसपर पूर्ण चर्चा एवम् विशेषज्ञों की राय
4. भारत दश में नए कानूनों के बावजूद महिलाओं पर अत्याचार और गुमशुदगी पर गहन चिंतन और विशेषज्ञों के विचार

इस समारोह में भारत देश के ज्वलंतशील मुद्दों पर जानकारी प्राप्त कर समाचार पत्रों द्वारा जनहित में जनता को सचेत करने और उससे जनता की सुरक्षा संभव के लिए *"परिवहन विशेष" " समर्पित एवं पूर्ण रूप से प्रयासरत रहेगा। इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष का वार्षिक समारोह ज्वलंतशील मुद्दों को समर्पित किया गया है। इस समारोह में भारत देश से विशेषज्ञों के साथ - साथ हमारा प्रयास भारत सरकार के माननीय गणमान्य कैबिनेट एवं राज्य स्तरीय मंत्रियों की गरिमा पूर्ण उपस्थिति और उनके विचार जनहित में मुख्य बिंदुओं में रहेगा।

इस समारोह में भारत देश में जनहित में इन कार्यों को करने में पूर्ण निष्ठा से सलग्न "सामाजिक कार्यकर्ताओं और कार्यरत समूहों (एनजीओ, ट्रस्ट एवं एसोसिएशन) को पुरस्कार" देकर सम्मानित किया जाएगा।

आपकी उपस्थिति हमारा गर्व

TRANSPORT VISHESH NEWS LIMITED
www.newsparivahan.com, www.newstransport.in

टेंपल्स आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) वैष्णवी फाउंडेशन एवं द्वारका स्थित मैक्स सुपर हॉस्पिटल के सौजन्य से

"पूर्णता निःशुल्क, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, स्वास्थ्य जाँच शिविर
आपकी तंदुरुस्ती हमारा ध्येय, टोलवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित

पूर्णतः निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर

संजय कुमार बाठला
राष्ट्रीय अध्यक्ष,

* वैष्णवी फाउंडेशन के सहयोग द्वारा

1. आंखों की जांच, 2. रक्तचाप, 3. मधुमेह जांच, 4. मोतियाबिंद सर्जरी के साथ-साथ 5. भारतीय लेंस की सुविधा * द्वारका स्थित मैक्स सुपर हॉस्पिटल के सहयोग द्वारा 6. बीपी, 7. शुगर, 8. कोलेस्ट्रॉल, 9. हड्डियों का घनत्व,

इस जांच शिविर मे ऊपरलिखित सभी जांच पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
इस जांच शिविर में निम्नलिखित अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टर्स एवम् अन्य की निगरानी में जांच,

वैष्णवी फाउंडेशनः 1. डॉ मनोज कुमार दुबे, 2. रिशु भारद्वाज, एवं 3. विकास राय द्वारका स्थित मैक्स सुपर हॉस्पिटल चिकित्सक 4. जगदीश

जांच शिविर : दिनांक: 15 मार्च (रविवार) 2026
स्थानः गुरुद्वारा सिंह सभा, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, शिवाजी एन्क्लेव, दिल्ली 110027
समय: 10:00 AM to 02:00 PM

आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में समय पर पधारें तथा अपने सगे-संबंधियों और मित्रों को भी साथ लेकर आएँ और इस अवसर का लाभ उठाएँ।
विशेष जानकारी मोतियाबिंद सर्जरी के साथ-साथ भारतीय लेंस की सुविधा के लिए मरीज को अपने खर्चे पर बालाजी हॉस्पिटल लायन्स हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा, पर सर्जरी और भारतीय लेंस निशुल्क रहेगा।
स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। आपकी सेहत- हमारी प्राथमिकता।

निवेदक :-
संजय कुमार बाठला-राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिंकी कुंडू-महासचिव, केके छाबड़ा-उपाध्यक्ष, सुनीता शर्मा-सचिव, अभिषेक राजपूत-सचिव

पिंकी कुंडू
महासचिव

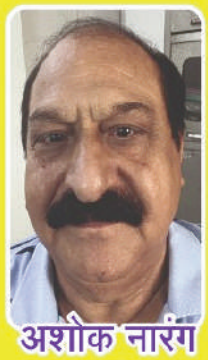
अशोक नारंग
उपाध्यक्ष

के.के. छाबड़ा
उपाध्यक्ष

सुनिता शर्मा
निजि सचिव (महासचिव)

अभिषेक राजपूत
सचिव

जयभगवान
सदस्य

अगर आप भारत देश में निम्नलिखित कार्यों में जनहित को समर्पित है तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं 'परिवहन विशेष' समाचार पत्र के तृतीय वार्षिक सम्मान समारोह में सम्मान

"सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा"
आज ही अपना आवेदन प्रक्रिया पूरी करे, यह बिल्कुल निशुल्क है,
अगर आपकी प्रतिभा इसे प्राप्त करने में सक्षम है तो आवेदन करे
https://www.newsparivahan.com/chief-editor/https://forms.gle/6tTqg7JX4EHGy2Cw9
मुख्य संपादक (परिवहन विशेष)

तृतीय वार्षिक सम्मान समारोह - 2026

परिवहन विशेष
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा
के जनहित कार्यों को समर्पित

20 सड़क सुरक्षा
महिला सुरक्षा
प्रदूषण
साइबर अपराध

अगर आप इन क्षेत्रों में जनहित को समर्पित हैं और आपकी प्रतिभा सक्षम है, तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं सम्मान। आज ही बिल्कुल निशुलक आवेदन करें।

दिनांक: 29 मार्च (रविवार) समय - दोपहर 1 बजे 5 बजे तक।
स्थान - कंस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली, 110001

आवेदन प्रक्रिया
https://forms.gle/6tTqg7JX4EHGY2Cw9

मुख्य संपादक - परिवहन विशेष

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल करें घरेलू उत्पाद, खिल जाएगी आपकी त्वचा : शहनाज़ हुसैन

चेहरा धोने के लिए हम ज्यादातर नामी कम्पनियों के महंगे उत्पादों पर भरोसा करते हैं / बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लुभावने विज्ञापनों के जाल में फंस कर हम महंगे उत्पादों को खरीद लेते हैं जिनमे केमिकल्स होते हैं और उनको लगाने से चेहरे पर दाग , धब्बे उभरने शुरू हो जाते हैं और कुछ मामलों में कील , मुहांसे भी उभर आते हैं / ऐसे में चेहरा बदसुरत दिखना शुरू हो जाता है और हम टेंशन में आ जाते हैं / मेरा यह मानना है की अगर हम घरेलू हर्बल उत्पादों का चेहरा धोने में उपयोग करें तो कहीं बेहतर परिणाम नज़र आएंगे और जेब पर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा /

1 दूध ----

हल्दी.दूध फेस पैक

हल्दी और दूध का फेस पैक बनाने के लिए आधा छोटा चम्मच हल्दी में दो छोटा चम्मच दूध मिलाएं/ इसे अच्छी तरह से मिलाकर फेस पैक की तरह चेहरे पर अप्लाई करें/

फेस पैक को सूखने दें/ हल्के हाथों से रब करते हुए पानी से त्वचा को साफ कर लें/

हल्दी और दूध का फेस पैक को बनाने के लिए 2 चम्मच कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी डालकर अच्छे से मिश्रण बना लें / इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर आधा घण्टा तक छोड़ दें/

अब चेहरे को सामान्य ताजे पानी से लें / बेहतर परिणाम के लिए इस पैक को हफ्ते में दो या तीन बार लगाएं/

कच्चे दूध को कॉटन पैड की मदद से चेहरे पर लगाए और पांच मिनट तक चेहरे की क्लींजिंग करें / इसके बाद चेहरे को साफ़ ताजे पानी से धो डालें / कच्चा दूध कील मुहांसों को हटाने में मददगार सावित होता है और इसके नियमित इस्तेमाल से चेहरा कोमल और मुलायम हो जाता है /

2 --------दही ------

दही स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होती है। आप दही को चेहरे पर किसी भी समय लगा सकते हैं। लेकिन चेहरे पर दही लगाने का सबसे सही समय सुबह और रात का है। अगर आप रोज सुबह चेहरे पर दही लगाएंगे, तो इससे त्वचा दिनभर फ्रेश और खिली-खिली नजर आएगी। रात में चेहरे पर दही लगाने से, त्वचा पर मौजूद सारी गंदगी और धूल-मिट्टी आसानी से निकल जाती है। इससे त्वचा पूरी तरह से साफ हो जाती है। इसलिए आपको सुबह और रात को चेहरे पर दही जरूर लगानी चाहिए।

पुराने समय से दही में बेसन और हल्दी मिक्स करके इस्तेमाल किया जा रहा है। आप भी 2 चम्मच दही लें। इसमें 2 चम्मच बेसन और चुटकी भर हल्दी मिलाएं। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। 20-25 मिनट बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। बेहतर रिजल्ट के लिए आप कुछ दिनों तक रोजाना चेहरे पर दही लगा सकते हैं। दही, बेसन और हल्दी का फेस पैक स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह पेस्ट सभी स्किन टाइप के लोगों के लिए अच्छा होता है। दही त्वचा को मुलायम बनाती है और बेसन त्वचा से अतिरिक्त तेल को सोखने में मदद करता है।

3 ----एलो वेरा जेल से चेहरा साफ़ करें ----------

ऐलोवेरा को घरेलू उपचार के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है ऐलोवेरा जैल या जूस को त्वचा पर सीधा अप्लाई किया जा सकता है। पौधे से निकाला गया जैल पत्ते की लुगदी होती है तथा पत्तियों के अंदरूनी हिस्सों में पाई जाती है। पत्तियों के बाहरी भाग के नीचे से ऐलो जूस निकाला जाता है। ऐलोवेरा को घरेलू उपचार के तोर पर प्रयोग करने में पहले पौधे को पूरी तरह धो लेना चाहिए तथा पूरी स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए।

ऐलोवेरा जूस या जैल को प्रतिदिन चेहरे पर 20 मिनट तक लगाकर साफ ताजे पानी से धो डालना चाहिए। यह त्वचा को मुलायम तथा आर्द्रता बनाए रखने में मदद करता है। यदि इसका नियमित रूप से सेवन किया जाए तो यह त्वचा के यौवन को बरकरार रखने में मददगार साबित होता है।

त्वचा में नमी प्रदान करने के लिए एक कटोरी में दो चम्मच एलो वेरा जैल और दो चम्मच बादाम तेल मिलाकर सोने से पहले चेहरे पर लगा लें

ऐलोवेरा गर्मियों में विशेष रूप से लाभदायक

साबित होता है क्योंकि यह त्वचा के रूखेपन को दूर करके त्वचा की मुलायम संरचना को बरकरार रखता है। यह सूर्य की गर्मी से प्रभावित त्वचा को शांत करने में भी मदद प्रदान करता है। यह त्वचा को तैलीय बनाए बगैर त्वचा में नमी को बनाए रखने में मदद प्रदान करता है।

4 ---शहद से चेहरा साफ़ करें-----

शहद का इस्तेमाल मास्क से लेकर नेचुरल मॉइश्चराइज़र के रूप में किया जा सकता है हमारी त्वचा को नमी चाहिए होती है।

मॉइस्चराइजर त्वचा को कोमल , स्वास्थ्यबर्धक और आकर्षक बनाए रखता है

दो तीन चमच्च कच्चा दूध और इतनी ही मात्रा में कच्चा शहद लेकर इसका मिश्रण बना लें / इस मिश्रण को अपने चेहरे , गर्दन और शरीर के खुले भागों पर लगाए और अपनी उँगलियों से सर्कुलर मोशन में मालिश करें तथा आधा घण्टा बाद पानी से धो डालें /आप इसे दिन में दो बार उपयोग में ला सकते हैं

अगर आपकी शुष्क त्वचा है तो एक चमच्च ताजे दही में आधा चमच्च कच्चा शहद मिलाकर बने मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर लगा कर 10 - 15 मिनट तक मालिश करें / इसे थोड़े देर बाद पानी से धो डालें / आप इसे दो तीन दिनों तक नियमित रूप से लगा सकती हैं और यह आपकी त्वचा की रंगत में निखार लाने के साथ ही त्वचा को कोमल और मुलायम भी बनाएगा /

अगर आप मुलायम त्वचा पाना चाहती हैं तो शहद का उपयोग करें। यह त्वचा को पोषण देने का काम करता है। त्वचा पर शहद लगाने से त्वचा में निखार आना शुरू हो जाता है /

अगर आपकी त्वचा शुष्क है तो आप अपने चेहरे पर केवल शहद लगा सकती हैं। कम से कम 20 मिनट बाद सादे पानी से चेहरा साफ कर लें। आप चाहें तो शहद में नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाकर इसका उपयोग कर सकती हैं। ऐसा करने से आपका चेहरा मुलायम के साथ.साथ प्रकृतिक रूप से चमकने लगेगा।

शहद से बना मास्क त्वचा को कई तरह से लाभ पहुंचाता है। आप घर पर ही हनी मास्क बना सकती हैं जो कि सभी प्रकार की त्वचा के लिए लाभदायक साबित होगा

लेखिका अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौन्दर्य विशेज्ञ है और हर्बल क्वीन के रूप में लोक प्रिय है

सहजन की फली (Drumstick), जिसे 'मुनगा' भी कहा जाता है

पिंकी कुंडू

सहजन की फली ना केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। सरसों के मसाले वाली पारंपरिक उत्तर भारतीय स्टाइल की रेसिपी:

सहजन की मसालेदार सब्जी (Sahjan ki Sabji)

सामग्री (Ingredients):

* सहजन: 250 ग्राम (2-3 इंच के टुकड़ों में कटी और छील ली गई)
* आलू: 2 मध्यम (लंबे कटे हुए)
* प्याज: 1 बारीक कटा हुआ
* टमाटर: 2 पिसे हुए या बारीक कटे हुए
* तेल: 2-3 बड़े चम्मच (सरसों का तेल सबसे अच्छा रहता है)

मसाला पेस्ट के लिए:

* पीली/काली सरसों: 2 बड़े चम्मच
* लहसुन: 8-10 कलियाँ
* अदरक: 1 इंच का टुकड़ा
* हरी मिर्च: 2-3

सूखे मसाले:

* हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच
* लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच (स्वादानुसार)
* धनिया पाउडर: 1 बड़ा चम्मच
* नमक: स्वादानुसार
* हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

बनाने की विधि (Instructions):

* तैयारी: सबसे पहले सरसों, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को थोड़े से पानी के साथ पीसकर एक महीन पेस्ट बना लें।
* फ्राई करें: एक कढ़ाई में तेल गरम करें। इसमें सहजन और आलू डालकर 3-4 मिनट तक मध्यम आंच पर भूनें जब तक कि उन पर हल्का सुनहरा रंग न आ जाए। इन्हें निकालकर अलग रख दें।
* तड़का: उसी बचे हुए तेल में आधा चम्मच पचफोरन या जीरा डालें। अब बारीक कटा हुआ प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें।
* मसाला भूनें: अब इसमें तैयार किया हुआ सरसों वाला पेस्ट डालें। साथ ही हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर डालकर तब तक भूनें जब तक मसाला तेल न छोड़ने लगे। (अगर मसाला चिपक रहा हो, तो थोड़ा पानी छिड़कें)।
* टमाटर: अब टमाटर और नमक डालें। टमाटर के नरम होने और मसाले के अच्छी तरह पकने तक भूनें।
* पकाना: भुने हुए आलू और सहजन को मसाले में मिलाएं। इसमें 1.5 से 2 कप पानी डालें (तरी आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं)।
* दम देना: कढ़ाई को ढक दें और मध्यम आंच पर 10-12 मिनट तक पकाएं, जब तक कि सहजन और आलू पूरी तरह गल न जाएं।
* फिनिशिंग: अंत में बारीक कटा हरा धनिया ऊपर से डालें और गैस बंद कर दें।

प्रो टिप (Pro Tip):

> सहजन को ज्यादा न पकाएं वरना वे रेशेदार होकर बिखर सकते हैं। सरसों का मसाला भूनते समय ध्यान रखें कि आंच धीमी हो, ताकि वह कड़वा न हो।

>

इसे गरमा-गरम चावल या फुल्के के साथ परोसें।

खुबानी एक स्वादिष्ट फल

पिंकी कुंडू

फल हमारे आहार का अहम स्त्रोत हैं, जिनमें खुबानी एक स्वादिष्ट फल हैं, जो ज़रूरी विटामिन, मिनरल और फ़ाइबर होते हैं जो पूरी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अपनी डाइट में खुबानी को शामिल करने से पाचन बेहतर होता है, दिल मज़बूत होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है, आइए जानते हैं इसके सेवन के फायदों के बारे में-

दिल की सेहत के लिए अच्छा खुबानी में पोटैशियम और फ़ाइबर भरपूर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्थिर रखने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। पाचन में मदद करता है खुबानी में मौजूद घुलनशील और अघुलनशील फ़ाइबर पाचन को आसान बनाते हैं और कब्ज़ से बचाते हैं।

स्किन की सेहत के लिए अच्छा खुबानी विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स है, जो स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और उसे फ्री रेडिकल्स से बचाता है।

आँखों की सेहत के लिए अच्छा विटामिन A की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से, खुबानी आँखों की बीमारियों को रोकने और नज़र को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करती है।

इम्यूनिटी को मज़बूत करता है खुबानी में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है।

बवासीर यानी पाइल्स

पिंकी कुंडू

बवासीर यानी पाइल्स एक आम लेकिन बेहद तकलीफदेह बीमारी है, जो ज्यादातर अनियमित जीवनशैली, कब्ज और गलत खानपान के चलते होती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को मल त्याग में जलन, खून आना और दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।हालांकि बाजार में इसकी कई दवाएं मौजूद हैं, लेकिन देसी चीजों से भी इससे राहत पा सकते हैं।

1. अंजीर (सूखा अंजीर)
अंजीर में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। रात को दो-तीन सूखे अंजीर पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट खाएं। इससे मल त्याग आसान होता है और बवासीर के दर्द से राहत मिलती है।

2. त्रिफला चूर्ण
त्रिफला एक आयुर्वेदिक चूर्ण है जो हरड़, बहड़ा और आंवला से बना होता है। यह कब्ज दूर करता है और आंतों की सफाई करता है। रात को सोने से पहले एक चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें, इससे बवासीर में काफी राहत मिलती है।

3. एलोवेरा एलोवेरा जेल
सूजन और जलन को कम करने में मदद करता है। एलोवेरा का ताजा जेल बवासीर प्रभावित स्थान पर लगाने से आराम मिलता है। साथ ही, सुबह खाली पेट थोड़ा एलोवेरा जूस पीना भी लाभदायक होता है।

4. छाछ और अजवाइन
छाछ पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और शरीर की गर्मी को संतुलित करता है। छाछ में चुटकी भर अजवाइन और काला नमक मिलाकर दिन में दो बार पीने से बवासीर में आराम मिलता है। यह गैस, कब्ज और सूजन को भी दूर करता है।

5. तिल और गुड़
पुराने समय से ही तिल और गुड़ का मिश्रण बवासीर में लाभकारी माना गया है। तिल कब्ज को दूर करते हैं और गुड़ पाचन में सुधार करता है। रोजाना सुबह एक चम्मच तिल और गुड़ मिलाकर खाने से बवासीर की तीव्रता में कमी आती है।

आयुर्वेद के अनुसार दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए

आयुर्वेद क्या कहता है - बहुत सारे लोग हमसे यह सवाल पूछते हैं कि दिन भर में खाना कितनी बार खाना सही रहता है। क्या सिर्फ दो बार भरपेट खाना बेहतर है, या फिर थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए कुछ लोग हर १–३ घंटे में हल्का-हल्का खाना यानी small frequent meals को सही मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि दिन में सिर्फ दो बार खाना ही शरीर के लिए बेहतर होता है।

असल में इन दोनों तरीकों के पीछे एक ही मकसद होता है—पाचन तंत्र को सही रखना और शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को संतुलित बनाए रखना।

अगर कोई व्यक्ति दिन में सिर्फ दो बार भरपेट भोजन करता है, तो शरीर को उस भोजन को ठीक से पचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे पाचन क्रिया आराम से काम करती है।

दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति थोड़ी-थोड़ी देर में कम मात्रा में खाता है, तो भी पेट पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ता क्योंकि एक समय में भोजन कम होता है।

अब सवाल यह है कि इन दोनों में से सही तरीका कौन सा है इसका जवाब आयुर्वेद के सिद्धांतों में मिलता है।

आयुर्वेद के अनुसार शरीर के तीन आधार

आयुर्वेद में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तीन मुख्य स्तंभ बताए गए हैं आहार (भोजन)
निद्रा (नींद)
ब्रह्मचर्य (संयमित जीवनशैली)

जैसे किसी मकान को मजबूत बनाए रखने के लिए मजबूत पिलर जरूरी होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन तीनों स्तंभों का संतुलित होना जरूरी है।

अगर इनका पालन सही तरीके से किया जाए, तभी शरीर लंबे समय तक स्वस्थ और स्थिर रह सकता है।

भोजन से जुड़ी भी आयुर्वेद में एक पूरी व्यवस्था बताई गई है जिसे आहार विधि विधान कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि कब, कितना और कैसे खाना चाहिए।

हर व्यक्ति के लिए नियम अलग क्यों होते हैं आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति अलग होता है। इसलिए भोजन से जुड़े नियम भी सभी के लिए एक जैसे नहीं हो सकते।

हर व्यक्ति में अलग-अलग चीजें अलग होती हैं, जैसे
शरीर की प्रकृति (वात, पित्त, कफ)
भूख लगने की तीव्रता
पाचन क्षमता
मौसम
उम्र
शारीरिक शक्ति
रोज़मर्रा की शारीरिक गतिविधि

इन सभी बातों के आधार पर यह तय होता है कि किसी व्यक्ति को दिन में कितनी बार खाना चाहिए।

प्रकृति के अनुसार भूख और पाचन

आयुर्वेद के अनुसार हमारी प्रकृति तीन दोषों पर आधारित होती है — वात, पित्त और कफ। इन दोषों के संतुलन के अनुसार पाचन शक्ति भी अलग-अलग होती है।

1. वात प्रकृति

वात प्रकृति वाले लोगों की अग्नि को विषम अग्नि कहा जाता है।

इसका मतलब है कि उनकी भूख स्थिर नहीं रहती—कभी बहुत तेज लगती है और कभी बिल्कुल नहीं लगती।

२. पित्त प्रकृति

पित्त प्रकृति वाले लोगों की अग्नि तीक्ष्ण अग्नि होती है।

इनकी भूख तेज होती है और पाचन भी तेज होता है। ये लोग खाना जल्दी पचा लेते हैं और उन्हें जल्दी फिर से भूख लग जाती है।

अगर ऐसे लोग सिर्फ दो बार खाने का नियम पकड़ लें और बीच में भूख लगने पर भी कुछ न खाएं, तो पित्त बढ़ सकता है। इसके कारण पेट में जलन, थकान और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

३. कफ प्रकृति

कफ प्रकृति वाले लोगों की अग्नि मंद अग्नि होती है।

इनकी भूख सामान्य से कम होती है और पाचन भी धीमा रहता है।

ऐसे लोगों के लिए दिन में दो बार खाना काफी अच्छा रहता है क्योंकि इससे भोजन को पचाने के लिए शरीर को पूरा समय मिलता है।

अगर कफ प्रकृति के लोग बार-बार थोड़ा-थोड़ा खाना शुरू कर दें, तो भोजन सही से पच नहीं पाता। इससे आम दोष बनता है, जो कई बीमारियों की जड़ माना जाता है।

बार-बार खाने से कौन-सी समस्याएं बढ़ सकती हैं अगर शरीर की ज़रूरत से ज्यादा बार भोजन लिया जाए और वह ठीक से पचे नहीं, तो इससे कई समस्याएं हो सकती हैं।

जैसे
वज़न बढ़ना
थकान
कम ऊर्जा
पाचन खराब होना

आयुर्वेद में शरीर की सप्त धातुएं बताई गई हैं
रस
रक्त
मांस
मेद
अस्थि
मज्जा
शुक्र

अगर मेद धातु (फैट) ज्यादा बढ़ने लगती है, तो उसके बाद बनने वाली धातुओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। इससे शरीर में कमजोरी और ऊर्जा की कमी महसूस होती है, भले ही वज़न बढ़ रहा हो।

भूख लगने पर ही खाना क्यों ज़रूरी है आयुर्वेद में 13 अधारनीय वेग बताए गए हैं। ये शरीर की प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं जिन्हें कभी दबाना नहीं चाहिए। इनमें शामिल हैं
भूख
प्यास
मल
मूत्र
छींक
जम्हाई आदि

अगर भूख लगी है तो उसे दबाना नहीं चाहिए, और अगर भूख नहीं लगी है तो जबरदस्ती खाना भी नहीं चाहिए। दोनों ही स्थितियाँ शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकती हैं और खासकर वात दोष को बढ़ा सकती हैं।

भोजन की मात्रा कैसे तय करें
आयुर्वेद में भोजन की मात्रा तय करने के लिए एक सरल नियम बताया गया है।

अगर भोजन गुरु (भारी) है यानी पचने में भारी है, तो उसे कम मात्रा में लेना चाहिए।

अगर भोजन लघु (हल्का) है, तो उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा भी ली जा सकती है।

उदाहरण के लिए, अगर सुबह आपने भारी भोजन किया है और फिर भी थोड़ी-थोड़ी देर में खाते रहे, तो यह पाचन के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।

ऐसी स्थिति में अगला भोजन हल्का रखना बेहतर होता है, जैसे मूंग की खिचड़ी।

मौसम के अनुसार भी बदलती है भूख, आयुर्वेद में साल को छह ऋतुओं में बांटा गया है
शिशिर
वसंत
ग्रीष्म
वर्षा
शरद
हेमंत

इन ऋतुओं के अनुसार शरीर की पाचन क्षमता भी बदलती रहती है।

हेमंत और शिशिर ऋतु में भूख अच्छी लगती है और शरीर भारी भोजन भी आसानी से पचा लेता है, लेकिन वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु में पाचन शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। खासकर वसंत में कफ बढ़ने के कारण अग्नि मंद हो जाती है।

इसलिए मौसम के अनुसार भोजन की मात्रा और संख्या में बदलाव करना चाहिए।

आपकी लाइफस्टाइल भी तय करती है भोजन की संख्या

अगर कोई व्यक्ति बहुत सक्रिय जीवन जीता है, जैसे
नियमित व्यायाम करता है
शारीरिक मेहनत वाला काम करता है
तो उसकी भूख ज्यादा होगी और वह दिन में तीन-चार बार भोजन भी आराम से पचा सकता है।

लेकिन जिन लोगों की sedentary lifestyle है, यानी ज्यादा समय बैठकर काम करते हैं और शारीरिक गतिविधि कम है, उनके लिए बार-बार खाना नुकसानदायक हो सकता है।

उम्र के अनुसार भी बदलता है पाचन

आयुर्वेद के अनुसार जीवन के अलग-अलग चरणों में दोषों का प्रभाव भी बदलता है।

बचपन — कफ प्रधान अवस्था
युवा अवस्था — पित्त प्रधान अवस्था
वृद्धावस्था — वात प्रधान अवस्था

युवा लोगों की पाचन शक्ति अच्छी होती है इसलिए वे ज्यादा बार भोजन पचा सकते हैं, लेकिन बच्चों और बुज़ुर्गों में भोजन की मात्रा और समय का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए।

आयुर्वेद को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे अपनाएं अगर इसे सरल तरीके से अपनाना हो तो कुछ बुनियादी नियम याद रखे जा सकते हैं।

नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

परिवहन विशेष

www.newsparivahan.com

वर्ष 03, अंक 371, नई दिल्ली, बुधवार 11 मार्च 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

"शब्दों से नहीं,व्यवहार से पहचान बनती है। क्योंकि अच्छे शब्दकुछ समय के लिए याद रहते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहारजीवन भर याद रहता है।

02 चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल करें घरेलू उत्पाद ---खिल जाएगी आपकी त्वचा - शहनाज़ हुसैन

06 भारत में बुजुर्ग माता-पिता से संबंधित कानूनी मुद्दे

08 पंजाब सरकार ने अपने बजट में अपने सभी चुनावी वादे पूरे किए: जसकरण सिंह बंदेशा

दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल पर बनेगा नया इंटरस्टेट बस टर्मिनल, राजधानी में बढ़ेगी

दिल्ली सरकार भलस्वा लैंडफिल साइट पर 20 एकड़ में नया डीटीसी इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनाने की योजना बना रही है। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने उत्तरी दिल्ली में कनेक्टिविटी सुधारने की बात कही।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉ. पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली सरकार भलस्वा लैंडफिल साइट पर लगभग 20 एकड़ ज़मीन पर एक नया DTC इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनाने का प्लान बना रही है। यह लैंडफिल साइट से साफ़ की जा रही जमीन पर प्रपोज किया गया है।

सिंह ने कहा कि प्रपोज्ड टर्मिनल से शहर के उत्तरी हिस्से में इंटरस्टेट बस कनेक्टिविटी और पैसेंजर सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है।

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-2) कॉरिडोर पर एक नया DTC डिपो बनाने के लिए एक फ़ीज़िबिलिटी स्टडी का निर्देश दिया ताकि तेजी से शहरी विस्तार और इलाके में बढ़ती ट्रांसपोर्टेशन की मांग को देखते हुए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएँ दी जा सकें।

मिनिस्टर ने अधिकारियों को बुराड़ी में मौजूदा बस डिपो को अपग्रेड करने का भी निर्देश दिया ताकि ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ाई जा सके और बढ़ते इलेक्ट्रिक बस फ्लीट को बेहतर तरीके से अकोमोडेट किया जा सके। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) के अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की।

फ्लीट में जल्द ही बसें जोड़ी जाएंगी 200 नई इलेक्ट्रिक

दिल्ली में अभी 4,000 से ज़्यादा EV बसें चलती हैं, और इस महीने, मार्च में, फ़्लीट में 200 और नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जाएंगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि इस साल के आखिर तक दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में 7,500 बसें पहुंचाने का टारगेट है, जो दिल्ली में सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक मील का पत्थर है।

दिल्ली में 44 बस डिपो पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है। PM ई-ड्राइव फेज I और फेज II इनिशिएटिव के तहत अभी 36 डिपो पर EV चार्जिंग नेटवर्क डेवलप किए जा रहे हैं।

अप्रैल में खुलेंगे दो ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन

नंद नगरी और तेहखंड में बन रहे ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) के अप्रैल में चालू होने की उम्मीद है, जिससे गाड़ी की फिटनेस टेस्टिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा और रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन पक्का करने में मदद मिलेगी।

लोक निवास में आधिकारिक कार्यक्रम के चलते 11 मार्च को यातायात रहेगा प्रभावित, एडवाइजरी जारी....

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 11 मार्च को लोक निवास में होने वाले आधिकारिक समारोह के लिए एडवाइजरी जारी की है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम के कारण सिविल लाइंस और आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रहेगा। कई सड़कों पर डायवर्जन लागू होंगे और वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोक निवास में 11 मार्च को होने वाले आधिकारिक समारोह के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की आवाजाही के कारण इलाके में ट्रैफिक संचालन प्रभावित रह सकता है। लोक निवास दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का आधिकारिक निवास है और यह सिविल लाइंस क्षेत्र में राज निवास मार्ग पर स्थित है।

समारोह के दौरान ITO चौक, रिंग रोड, मॉल रोड, राजपुर रोड, महात्मा गांधी मार्ग, चौबुर्जा मार्ग, भीकू राम जैन मार्ग, शमनाथ मार्ग, बुलेवार्ड रोड और लोक निवास मार्ग पर ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है। जरूरत पड़ने पर इन सड़कों से ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। डायवर्शन पॉइंट्स में पीएस सिविल लाइंस रेड लाइट, शमनाथ मार्ग रेड लाइट, तीस हजारी कोर्ट रेड लाइट, खोया मंडी यू-टर्न, खैबर पास रेड लाइट, सेंट स्टीफेंस रेड लाइट, राजपुर अथॉरिटी कट और एमसीडी चौक शामिल हैं।

वैकल्पिक मार्गों के उपयोग की सलाह

सामान्य वाहनों के अलावा सभी कमर्शियल वाहनों को राज निवास मार्ग पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केवल इमरजेंसी वाहनों को छूट दी जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे उपरोक्त सड़कों से बचें और सड़क किनारे पार्किंग न करें, क्योंकि इससे सामान्य ट्रैफिक प्रवाह में बाधा आती है। यातायात सुगम बनाए रखने के लिए पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपेक्षा की है। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें ताकि असुविधा कम हो।

दिल्ली के इस इलाके में सीवर लाइन कार्य से 15 दिन यातायात प्रभावित, क्या है वैकल्पिक मार्ग?

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सिविल लाइंस में राजपुर रोड पर सीवर लाइन बिछाने के काम के कारण 10 से 25 मार्च, 2026 तक 15 दिनों के लिए यातायात प्रभावित रहेगा।

परिवहन विशेष न्यूज

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, राजपुर रोड पर राजपुर अथॉरिटी कट से MCD चौक तक का हिस्सा सभी तरह के वाहनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन रेड लाइट और राजपुर अथॉरिटी कट से आने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह से डायवर्ट किया जाएगा।

नई दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के सीवर लाइन बिछाने के काम की वजह से 15 दिनों तक ट्रैफिक पर असर रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए एडवाइजरी जारी की है।

दिल्ली जल बोर्ड 10 मार्च से 25 मार्च, 2026 तक 31वें राजपुर रोड से 19वें राजपुर रोड, सिविल लाइंस तक 300 mm डायमीटर की सीवर लाइन बिछाएगा। यह काम सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन से MCD चौक तक के कैरिजवे पर किया जा रहा है। इस काम से राजपुर रोड, मॉल रोड, महात्मा गांधी मार्ग, चौबुर्जा मार्ग, भीकू राम जैन मार्ग, शामनाथ मार्ग और लोक निवास मार्ग पर ट्रैफिक जाम बढ़ सकता है।

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, राजपुर रोड पर राजपुर अथॉरिटी कट से MCD चौक तक का हिस्सा सभी तरह के वाहनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन रेड लाइट और राजपुर अथॉरिटी कट से आने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह से डायवर्ट किया जाएगा। तीस हजारी की ओर जाने वाली सभी गाड़ियों को भी इन दो जगहों से डायवर्ट किया जाएगा। MCD चौक से PS सिविल लाइंस रेड लाइट की ओर सिर्फ वन-वे ट्रैफ़िक चलेगा।

डायवर्जन के तहत, सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन की रेड लाइट से आने वाली गाड़ियां अपर अथॉरिटी कट से अंडर हिल रोड पर मुड़ सकेंगी और शामनाथ मार्ग और राज निवास रोड होते हुए MCD चौक जा सकेंगी। हालांकि, इस रूट पर कमर्शियल गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा, ड्राइवर शामनाथ मार्ग, बुलेवार्ड रोड और युधिष्ठिर सेतु के नीचे से यू-टर्न लेकर रानी झांसी रोड की ओर भी जा सकते हैं।

ट्रैफ़िक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की प्लानिंग करते समय बताए गए रास्तों से बचें और नॉर्मल ट्रैफ़िक फ़्लो बनाए रखने के लिए सड़क किनारे गाड़ियां पार्क न करें।

दिल्ली की हवा सुधारने के लिए 22 नई तकनीकें तैयार, प्रदूषण हॉटस्पॉट पर जल्द शुरू होगा ट्रायल

दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शुरू हुए 'इनोवेशन चैलेंज' से 22 अत्याधुनिक तकनीकें चुनी गई हैं। ये तकनीकें अब दिल्ली के प्रदूषण हॉटस्पॉट पर जमीनी ट्रायल के लिए तैयार हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग अब एक नए और आधुनिक चरण में प्रवेश कर गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शुरू किए गए "इनोवेशन चैलेंज" के तहत चुनी गई 22 अत्याधुनिक तकनीकें अब जमीनी ट्रायल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगले कुछ हफ्तों में इनको दिल्ली के प्रमुख प्रदूषण हाटस्पाट पर तैनात किया जाएगा।

वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और चयन प्रक्रिया

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इन तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस चैलेंज के लिए देश भर से कुल 284 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। गहन तकनीकी जांच और "इंटरनल टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी" की समीक्षा के बाद केवल 22 इनोवेटिव समाधानों को ही ट्रायल के लिए शार्टलिस्ट किया गया है।

दो श्रेणियों में बंटे हैं समाधान

इन 22 तकनीकों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:-

वाहन उत्सर्जन नियंत्रण (13 डिवाइस): इसमें बसों और ट्रकों के लिए व्हीकल-माउंटेड एयर प्यूरीफायर, रेट्रोफिट एमिशन-कंट्रोल सिस्टम और बायो-अल्कलाइन एग्जॉस्ट स्क्रबर शामिल हैं।

एम्बिएंट एयर प्यूरीफिकेशन (9 डिवाइस): ये खुले इलाकों, निर्माण स्थलों और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें डस्ट सप्रेशन यूनिट और स्मॉग-कंट्रोल जैसी तकनीकें शामिल हैं।

प्रमाण के आधार पर होगा चयन

पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य मानक "प्रमाण और डेटा" होगा। उन्होंने कहा, 'हम उन तकनीकों की पहचान करना चाहते हैं जो न केवल प्रभावी हों, बल्कि जिन्हें बड़े पैमाने पर दिल्ली में लागू करना व्यावहारिक हो। यह ट्रायल हमें सबसे हाई-इम्पैक्ट समाधान चुनने में मदद करेगा।'

ट्रायल के दौरान दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) डेटा कलेक्शन और परफार्मेंस रिव्यू पर करीबी नजर रखेगी। इन परीक्षणों के परिणामों के आधार पर ही भविष्य की क्लीन-एयर रणनीति का रोडमैप तैयार किया जाएगा।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html I
tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

पिंकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार: रूसी हैकर्स द्वारा WhatsApp और Signal के Linked Devices फीचर का दुरुपयोग

साइबर सुरक्षा रिपोर्ट: WhatsApp और Signal में Linked Devices का दुरुपयोग

खतरे का स्रोत: रूस समर्थित हैकर समूह

तारीख: मार्च 2026

1. पृष्ठभूमि

- WhatsApp और Signal दोनों एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) का उपयोग करते हैं, जिसे वर्तमान मानकों के अनुसार अभेद्य माना जाता है।

- लेकिन Linked Devices फीचर यूज़र्स को अपने अकाउंट से कई डिवाइस (डेस्कटॉप, टैबलेट, सेकेंडरी फोन) जोड़ने की अनुमति देता है।

- यह सुविधा सुविधाजनक होते हुए भी एक साइड-चैनल कमजोरी पैदा करती है: एक बार डिवाइस लिंक हो जाने पर, उसे सभी एन्क्रिप्टेड संदेश डिक्रिप्टेड रूप में मिल जाते हैं, जिससे एन्क्रिप्शन तोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती।

2. हमले का तरीका

- फ़िशिंग और सोशल इंजीनियरिंग: हैकर्स यूज़र्स को नकली QR कोड स्कैन करने या वेरिफिकेशन कोड साझा करने के लिए बहकाते हैं।

- फर्जी सपोर्ट बॉट्स: हमलावर Signal/WhatsApp सपोर्ट बनकर PIN या कोड मांगते हैं।

- साइलेंट डिवाइस लिंकिंग: एक बार लिंक होने पर, हमलावर का डिवाइस सभी बातचीत को रियल-टाइम में मिरर करता है।

- एन्क्रिप्शन सुरक्षित: यह हमला एन्क्रिप्शन को नहीं तोड़ता, बल्कि Linked Devices के भरोसेमंद मॉडल का दुरुपयोग करता है।

3. प्रभाव

- निशाना बनाए गए समूह:

- सरकारी अधिकारी

- सैन्यकर्मी

- पत्रकार

- राजनयिक और नीति-निर्माता

- जोखिम:

- संवेदनशील संचार की रियल-टाइम निगरानी

- गोपनीय या रणनीतिक जानकारी का लीक होना

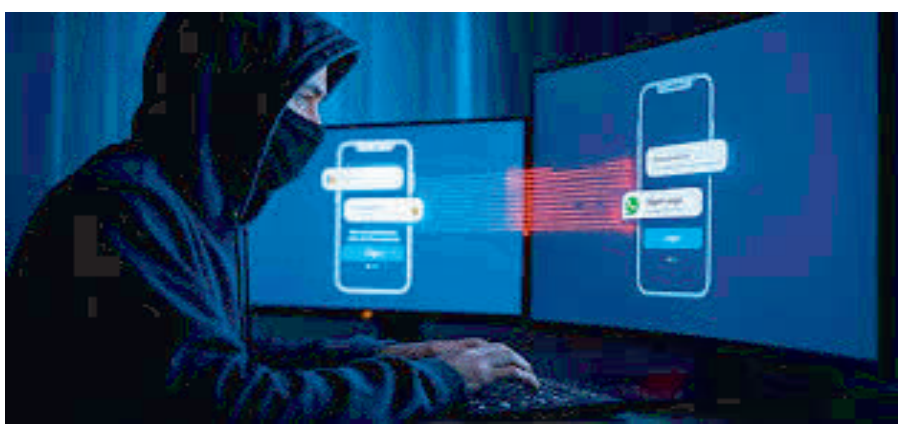

- पत्रकारिता की गोपनीयता कमजोर होना

- जनमत को प्रभावित करने की संभावना

4. बचाव के उपाय

- Linked Devices की जाँच करें:

- नियमित रूप से जुड़े हुए डिवाइसों की सूची देखें।

- किसी भी अज्ञात या संदिग्ध डिवाइस को तुरंत हटाएँ।

- Registration Lock / PIN सक्षम करें:

- अकाउंट ट्रांसफर पर अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ता है।

- जागरूकता और प्रशिक्षण:

- यूज़र्स को शिक्षित करें कि WhatsApp/Signal कभी चैट में कोड नहीं मांगते।

- अनचाहे QR कोड या "सपोर्ट" संदेशों पर संदेह करें।

- संस्थागत सुरक्षा:

- अधिकारियों के लिए नियमित अकाउंट सुरक्षा जाँच अनिवार्य करें।

- संदिग्ध लॉगिन प्रयासों की निगरानी लागू करें।

5. रणनीतिक निहितार्थ

- यह घटना साइबर युद्ध की रणनीति में बदलाव को दर्शाती है:

- एन्क्रिप्शन तोड़ने के बजाय, विरोधी यूज़र-साइड फीचर्स और मानवीय कमजोरियों का फायदा उठाते हैं।

- यह सुरक्षित संचार में ऑपरेशनल अनुशासन की आवश्यकता पर बल देता है।

- भारत और अन्य देशों के लिए यह हमला याद दिलाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल मजबूत तकनीक पर नहीं, बल्कि सतर्क उपयोग प्रथाओं पर भी निर्भर करती है।

6. निष्कर्ष

रूसी हैकर्स का यह अभियान दिखाता है कि केवल एन्क्रिप्शन पर्याप्त नहीं है। सबसे कमजोर कड़ी अक्सर यूज़र का Linked Devices जैसे फीचर्स के साथ इंटरैक्शन होता है। सतर्कता, जागरूकता और संस्थागत सुरक्षा ही ऐसे जासूसी प्रयासों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।

चिन्हित अपराधों से जुड़े मामलों में पीड़ितों को मिले त्वरित न्याय : डीसी

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 10 मार्च। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में चिन्हित अपराधों के मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाना है।

उपायुक्त ने चिन्हित अपराध से जुड़े मामलों और संवेदनशील कानूनों के तहत दर्ज केसों की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर उनकी सुनवाई और निपटान में तेजी लाई जाए। साथ ही गवाहों को समय पर समन भेजने तथा जांच अधिकारी की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में ऐसे मामलों की भी समीक्षा की गई जिनमें अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी मामले में न्याय के हित में अपील करना आवश्यक है तो संबंधित अधिकारी समयबद्ध तरीके से अपील की प्रक्रिया शुरू करना सुनिश्चित करें।

डीसीपी जसलीन कौर ने बैठक में बताया कि पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित अपराध से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

इस अवसर पर एसडीएम झज्जर अंकित चौकसे, जिला न्यायवादी अनुज दहिया, जेल अधीक्षक संदीप डांगी, सिविल सर्जन डॉ मंजू कादयान, डीडीपीओ निशा तंवर, डीईओ रतिंद्र सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

आत्मकथा 'अपनी राम कहानी' के लिए डॉ. सविता चड्ढा को मिलेगा 'साहित्य भूषण सम्मान'

डॉ. शंभु पंवार

नई दिल्ली, 10 मार्च। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मानों से अलंकृत प्रख्यात लेखिका डॉ. सविता चड्ढा को उनकी चर्चित आत्मकथा 'अपनी राम कहानी' के लिए इंडिया नेटबुक्स का प्रतिष्ठित 'साहित्य भूषण सम्मान' प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।

डॉ.चड्ढा को यह सम्मान बीपीए फाउंडेशन एवं इंडिया नेटबुक्स के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 'साहित्यकार सम्मान उत्सव' के अवसर पर 14 मार्च 2026 को दिल्ली के क्राउन प्लाजा, मयूर विहार डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा।

इंडिया नेटबुक्स के संस्थापक डॉ. संजीव कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस वर्ष विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट लेखन करने वाले देश के अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार ममता कालिया की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने सर्वसम्मति से डॉ. सविता चड्ढा को उनकी आत्मकथात्मक कृति 'अपनी राम कहानी' के लिए 'साहित्य भूषण सम्मान' हेतु चयनित किया है।

उल्लेखनीय है कि डॉ. सविता चड्ढा हिंदी साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी पहली पुस्तक 1984 में प्रकाशित हुई थी और अब तक उनकी 55 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी कहानियों पर नाट्य मंचन हो चुके हैं, टेलीफिल्मों का निर्माण भी किया गया है तथा उनकी पत्रकारिता संबंधी पुस्तकों को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। उनकी कहानियों पर विद्यार्थियों द्वारा शोध कार्य भी किए जा चुके हैं। डॉ. चड्ढा को वर्ष 1987 में हिंदी अकादमी, दिल्ली द्वारा 'साहित्य कृति सम्मान' तथा वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी, पंचकूला द्वारा 'हरियाणा गौरव सम्मान' से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस सम्मान के अंतर्गत उन्हें दो लाख रुपये की नगद राशि भी प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त देश-विदेश के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा समय-समय पर उन्हें उनके साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।

हिंदी साहित्य में उनकी निरंतर सक्रियता, बहुआयामी लेखन और रचनात्मक योगदान को देखते हुए 'साहित्य भूषण सम्मान' की यह घोषणा साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है।

डॉ. शंभु पंवार
(वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर)
अंतरराष्ट्रीय लेखक, पत्रकार व विचारक

खाद्य सुरक्षा के मानकों को सख्ती से लागू करे विभाग: डीसी

जिला स्तरीय फूड सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी की बैठक में डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने दिए सख्त निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 10 मार्च। लघु सचिवालय में मंगलवार को जिला स्तरीय फूड सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी की बैठक उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में आम नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जाए और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इस बीच फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ. राजेश वर्मा ने जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा समय-समय पर बाजारों, होटल-ढाबों, मिठाई की दुकानों, मिड डे मील, फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर उनकी जांच करवाई जाती है ताकि लोगों को मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थों से बचाया जा सके।

डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों, मेलों और विशेष अवसरों के दौरान बाजारों में विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी खाद्य व्यवसाय संचालक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) के नियमों का पालन करें और आवश्यक लाइसेंस व पंजीकरण करवाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई के मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए और जहां कहीं भी नियमों की अनदेखी पाई जाए वहां तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आम जनता को भी खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी अपने-अपने सुझाव रखे और खाद्य सुरक्षा को लेकर समन्वय के साथ कार्य करने की बात कही। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि जिले में खाद्य सुरक्षा के मानकों को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

इस अवसर पर एसडीएम झज्जर अंकित कुमार चौकसे, आईएएस, सिविल सर्जन डॉ मंजू कादयान, डीडीपीओ निशा तंवर, एएफएसओ अमरजीत सिंह, आईईओ सरिता रंगा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में डॉ. भीमराव अंबेडकर का ऐतिहासिक योगदान : अधिवक्ता सुनीता कल्सन

परिवहन विशेष न्यूज

बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा के चुनावों की सशक्त उम्मीदवार एवं नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स की सहसंयोजक अधिवक्ता सुनीता कल्सन ने महिलाओं की उन्नति में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के योगदान के बारे में एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि आज भारत में महिलाओं को जो संवैधानिक, सामाजिक और कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, उनकी मजबूत नींव भारत के महान विधिवेत्ता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने रखी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति का वास्तविक मापदंड यह है कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। यह विचार उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी था, जब भारतीय समाज गहरी पितृसत्तात्मक मानसिकता और अनेक सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था।

अधिवक्ता कल्सन ने कहा कि डॉ. अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज में वास्तविक लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हों। इसलिए उन्होंने महिलाओं की समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक आंदोलनों, वैचारिक लेखन और कानूनी सुधारों के माध्यम से निरंतर संघर्ष किया।

अपने प्रसिद्ध शोधपत्र ","Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development"1916 में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महिलाओं की स्वतंत्रता को नियंत्रित किया गया। इसी प्रकार उनकी प्रसिद्ध कृति , "Annihilation of Caste","1936 में उन्होंने यह बताया कि जाति व्यवस्था केवल सामाजिक असमानता ही नहीं पैदा करती, बल्कि यह महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता को भी बाधित करती है। अपने लेख ,"The Rise and Fall of Hindu Women" में उन्होंने यह भी बताया कि प्राचीन भारत में महिलाओं को अपेक्षाकृत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, लेकिन समय के साथ सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के कारण उनकी स्थिति कमजोर होती चली गई।

भारत की आजादी के बाद जब नए राष्ट्र के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, तब डॉ. अंबेडकर ने भारत के संविधान के निर्माण में यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को पुरुषों के समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त हों। संविधान में समानता, लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, समान काम के लिए समान वेतन तथा मातृत्व राहत जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए, जिनसे महिलाओं को संवैधानिक सुरक्षा और समानता का मजबूत आधार मिला।

उन्होंने कहा कि 1942 से लेकर 1946 के बीच जब डॉ. अंबेडकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री थे, तब उन्होंने महिला श्रमिकों के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। उन्होंने फैक्ट्रियों में काम के घंटे 12 से घटाकर 8 घंटे करने का निर्णय लिया और महिला मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ तथा कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधान लागू करवाए। इन सुधारों ने महिला श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों को अधिक मानवीय और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में डॉ. अंबेडकर का सबसे क्रांतिकारी प्रयास हिन्दू कोड बिल था। इस विधेयक के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार, विवाह में समानता, तलाक का अधिकार, विधवाओं को संपत्ति का अधिकार और गोद लेने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा। उस समय के रूढ़िवादी वर्गों के भारी विरोध के कारण यह बिल तत्काल पारित नहीं हो सका और अंततः डॉ. अंबेडकर ने 1951 में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में इसी बिल के आधार पर "Hindu Marriage Act 1955, Hindu Succession Act 1956, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 जैसे महत्वपूर्ण कानून बने, जिन्होंने भारतीय महिलाओं को विवाह, संपत्ति और पारिवारिक अधिकारों के क्षेत्र में नई स्वतंत्रता प्रदान की।

उन्होनें कहा कि डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से भी महिलाओं को जागरूक और संगठित किया। 1927 में हुआ महाड़ सत्याग्रह सामाजिक समानता के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इसी आंदोलन के दौरान मनुस्मृति दहन का आयोजन किया गया, जो उन विचारों के विरोध का प्रतीक था जिनमें महिलाओं और दलितों को निम्न और अधीन माना गया था।

जिला के 124 गांव और 15 वार्ड नशा मुक्त घोषित

जिला एनकॉर्ड बैठक आयोजित, जिला को शत प्रतिशत नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य

परिवहन विशेष न्यूज

डीसी बोले- नशे के खिलाफ प्रशासन, पुलिस व समाज को मिलकर करना होगा
गांव व वार्ड स्तर की टीमें एक्टिव मोड में करें कार्य, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुहिम से जोड़ें

झज्जर, 10 मार्च। जिले को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर मंगलवार को लघु सचिवालय में डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति (एनकॉर्ड) की मासिक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में डीसीपी जसलीन कौर भी मौजूद रही व सभी एसडीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

डीसी ने कहा कि जिला के 124 गांवों और 15 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया जा चुका है। सभी गांवों को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर आपसी समन्वय से कार्य करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर उपमंडल स्तर पर नशा मुक्ति अभियान को तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि गांव और वार्ड स्तर पर पहले से गठित टीमों को एक्टिव मोड में लाया जाए और एसडीएम इन टीमों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जाए और जागरूकता कार्यक्रमों को निरंतर चलाया जाए।

डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसलिए जरूरी है कि प्रशासन, पुलिस, पंचायतें और समाज सेवी संस्थाएं मिलकर इस दिशा में काम करें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अवेयरनेस कैंपेन आयोजित करें, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम सभाओं में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाए।

उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ब्लाक स्तर पर बॉलीबाल सहित अन्य खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी।

डीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल स्टोर्स पर कड़ी निगरानी रखी जाए और डॉक्टर की पर्ची के बिना प्रतिबंधित दवाइयां न बेची जाएं। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

डीसीपी जसलीन कौर ने बैठक में बताया कि पुलिस द्वारा लगातार नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, गांव-गांव जाकर युवाओं को जागरूक करने के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हर गांव को नशा मुक्त बनाना है। इस अवसर पर एसडीएम आईएएस अंकित कुमार चौकसे, जिला अटॉर्नी अनुज दहिया, जेल अधीक्षक संदीप डांगी, सिविल सर्जन डॉ मंजू कादयान, डीडीपीओ निशा तंवर, डीईओ रतिंद्र सिंह, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय बालक (हिसार) में माता सावित्रीबाई फुले की 129वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

सावित्रीबाई फुले, महाक्रांति की जननी और आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका*
समानता केवल संविधान में नहीं, हमारे व्यवहार में होनी चाहिए।
क्रांति वह है जो समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछ सके।
नमन है उस महानायिका को, जिसने अपने अपमान की राख से भारत की स्त्री शिक्षा का सूर्य उगाया।
महिलाओं की शिक्षा और समानता की अग्रदूत थी सावित्रीबाई फुले
सावित्री बाई फूले का संघर्ष समाज के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत

हिसार/हरियाणा (नरेश गुणपाल)

ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय बालक (हिसार) में आज देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की 129वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उनके संघर्षपूर्ण जीवन और महिलाओं के अधिकारों के लिए किए गए ऐतिहासिक योगदान को याद किया गया।

जब भारतीय समाज की अज्ञानता के विरुद्ध युद्ध करने वाली महान सेनापति क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले ने मानवता की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी।*

आज उनकी पुण्यतिथि पर, हम न केवल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, बल्कि उनके उस क्रांतिकारी विचार को नमन करते हैं, जिसने करोड़ों महिलाओं और वंचितों के हाथों में 'कलम' रूपी शस्त्र थमाया।

भारत का इतिहास राजाओं और युद्धों के वृत्तांतों से भरा पड़ा है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के इतिहास में सावित्रीबाई फुले का नाम उस ध्रुवतारे की तरह है, जिसने घोर अंधकार में भटकते समाज को दिशा दिखाई।

जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि

सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव नायगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खन्दोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मीबाई था।

मात्र 9 वर्ष की आयु में 1840 में उनका विवाह महात्मा ज्योतिराव फुले से हुआ। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि दो महान क्रांतिकारी विचारधाराओं का मिलन था, जिसने आगे चलकर भारतीय समाज की चूलें हिला दीं।

शिक्षा का कुरुक्षेत्र

जिस दौर में शूद्रों और महिलाओं के लिए विद्या ग्रहण करना 'पाप' समझा जाता था, उस दौर में सावित्रीबाई ने शिक्षा का बिगुल फूंका।

1 जनवरी 1848 को पुणे के 'भिड़ेवाड़ा' में जब उन्होंने महिलाओं एवं दलितों के लिए पहली पाठशाला खोली, तो वे केवल गणित या व्याकरण नहीं पढ़ा रही थीं, बल्कि वे 'समानता' का पाठ पढ़ा रही थीं।

सड़कों पर चलते समय रूढ़िवादी लोग उन पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंकते थे। वे उन्हें गालियां देते थे, लेकिन सावित्रीबाई शांत भाव से कहती थीं

मेरे भाई, तुम मुझ पर पत्थर और गोबर फेंककर मेरा मनोबल बढ़ा रहे हो। तुम मुझे यह याद दिला रहे हो कि मुझे अभी और कितनी मेहनत करनी है।

वे अपने साथ थैले में एक अतिरिक्त साड़ी रखती थीं। कीचड़ से सनी साड़ी को स्कूल पहुंचकर बदल लेतीं और फिर से छात्राओं के भविष्य को संवारने में जुट जातीं। उनके इसी अटूट संकल्प ने आज भारत की हर शिक्षित बेटी के लिए रास्ता खोला है।

सामाजिक न्याय का क्रांतिकारी शंखनाद

सावित्रीबाई फुले का कार्यक्षेत्र केवल स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं था। वे एक संपूर्ण समाज सुधारक थीं

सत्यशोधक समाज

उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर *सत्यशोधक समाज' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद को जड़ से मिटाना था।*

उन्होंने पुरोहितों के बिना विवाह की परंपरा शुरू की, जिसे 'सत्यशोधक विवाह' कहा गया।

मानवीय गरिमा और अधिकार

जब अछूत माने जाने वाले वर्गों को प्यासा रखा जाता था, तब सावित्रीबाई ने अपने घर का पानी का हौज सबके लिए खोल दिया।

यह उस समय का सबसे बड़ा विद्रोह था।

नारी मुक्ति का स्वर

उन्होंने 'बाल हत्या प्रतिबंधक गृह' की स्थापना की। समाज द्वारा तिरस्कृत विधवाओं और उनके बच्चों को न केवल आश्रय दिया, बल्कि एक विधवा के पुत्र (यशवंत) को गोद लेकर उसे डॉक्टर बनाया और समाज के सामने उदाहरण पेश किया।

काव्य और लेखन

सावित्रीबाई एक प्रखर कवयित्री थीं। उनकी रचनाएं 'काव्य फुले' और 'बावनकशी सुबोध रत्नाकर' आज भी क्रांति का संचार करती हैं।

उन्होंने कहा था

"स्वयं को जानो, शिक्षा प्राप्त करो, अज्ञानता की बेड़ियों को तोड़ दो और स्वाभिमान के साथ जियो।"

शहादत: सेवा की पराकाष्ठा

1897 में जब पुणे में 'प्लेग' की भयंकर महामारी फैली, तो 66 वर्ष की उम्र में भी सावित्रीबाई घर में दुबक कर नहीं बैठीं। वे खुद मरीजों के पास जातीं, उनकी सेवा करतीं और उन्हें अस्पताल पहुँचातीं।

एक दलित बच्चे को, जो प्लेग से पीड़ित था, अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल ले जाते समय वे स्वयं संक्रमित हो गईं।

10 मार्च 1897 को इसी सेवा भाव के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली।

आज हमारा संकल्प

सावित्रीबाई फुले को सच्ची श्रद्धांजलि केवल फोटो पर फूल चढ़ाने से नहीं, बल्कि उनके विचारों को जीने से मिलेगी।

आज जब हम आधुनिक समाज की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि, शिक्षा केवल डिग्री लेना नहीं, बल्कि तर्कशील होना है।

ओडिशा में सहकारी डिजिटल अवसंरचना को मिला बढ़ावा, एकीकृत आरसीएस डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ

संगिनी घोष,

ओडिशा में सहकारी क्षेत्र को डिजिटल रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एकीकृत रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज (RCS) डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है।

यह पोर्टल 6 मार्च 2026 से लाइव हो चुका है और इसके माध्यम से सहकारी समितियों के प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया गया है। इस पहल से सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित और सुलभ होने की उम्मीद है।

अधिकारियों के अनुसार, National Cooperative Database (NCD) के साथ एकीकरण के लिए एपीआई (API) विकसित करने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इसके माध्यम से सहकारी संस्थाओं से संबंधित आंकड़ों का बेहतर प्रबंधन और समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

ओडिशा राज्य की सभी सहकारी समितियों को पहले ही एनसीडी पोर्टल पर ऑनबोर्ड कर दिया गया है, जिससे एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया है। इससे सहकारी क्षेत्र में निगरानी और निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

वहीं, देश के अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी इसी प्रकार की परियोजनाओं का कार्यान्वयन जारी है। कुछ राज्यों में यह परियोजना हाल ही में पूर्ण हुई है और वहां आरसीएस कार्यालयों के कार्यों में हुए सुधारों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

ऐसे देखें तो यह पहल सहकारी क्षेत्र को डिजिटल रूप से मजबूत करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता व दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

* ओडिशा में एकीकृत आरसीएस डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ

* पोर्टल 6 मार्च 2026 से लाइव

* National Cooperative Database (NCD) के साथ एकीकरण के लिए API विकास जारी

* राज्य की सभी सहकारी समितियां NCD पोर्टल पर ऑनबोर्ड

* कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में परियोजना का कार्यान्वयन जारी

* सहकारी प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने का प्रयास

SEO Meta Description:

ओडिशा में सहकारी डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए एकीकृत RCS डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे सहकारी समितियों के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मां सीता रसोई ने किया महिलाओं का सम्मान

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाली महिलाएं हुईं ₹सनातन नारी शक्ति सम्मान₹ से अलंकृत

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। परिक्रमा मार्ग/ज्ञान गुदड़ी स्थित श्रीपंच हरिव्यासी महानिर्वाणी निर्मोही अखाड़ा (छत्तीसगढ़ कुंज) में श्रीतुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की प्रेरणा से मां सीता रसोई के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ₹सनातन नारी शक्ति सम्मान समारोह₹ का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। जिसके अंतर्गत मां सीता रसोई की संस्थापक व संकट मोचन सेना (महिला प्रकोष्ठ) की अध्यक्ष ₹पंजाब रत्न₹ श्रीमती मनप्रीत कौर (लुधियाना), चित्रकूट स्थित श्रीतुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास महाराज एवं प्रख्यात भजन गायक चित्र-विचित्र महाराज के द्वारा प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना कुंजलता मिश्रा, कथक डांसर गीतांजलि (ब्रज की राधा), सब-इंस्पेक्टर, पुलिस अलका रानी, श्रीमती भारती देवी, प्रमुख भाजपा नेत्री श्रीमती सरोज गोला, ब्रज सेवा संस्थान की निदेशक श्रीमती वसुधा चतुर्वेदी, इशिता शर्मा, प्रियंका सिंह, ऐश्वर्या कौशिक, सनाया शर्मा एवं श्वेता चौहान आदि 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया।साथ ही प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र एवं ठाकुरजी का पटुका-प्रसादी-माला आदि भेंट कर उन्हें ₹सनातन नारी शक्ति सम्मान₹ से अलंकृत किया गया।

इस अवसर पर श्रीमज्जगद्गुरु विष्णुस्वामी विजयराम देवाचार्य भैयाजी महाराज (वल्लभगढ़ वाले), गोरीलाल कुंज के श्रीमहंत स्वामी किशोर दास देवजू महाराज, पीपाद्वाराचार्य जगद्गुरु बाबा बलरामदास देवाचार्य महाराज, महामंडलेश्वर महंत गोपीकृष्ण दास महाराज, पुराण मनीषी कौशिक जी महाराज, चतुःसंप्रदाय के श्रीमहंत फूलडोल बिहारीदास महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद शास्त्री,प्रख्यात साहित्यकार ₹यूपी रत्न₹ डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ब्रज भूमि कल्याण परिषद् के अध्यक्ष पण्डित बिहारीलाल वशिष्ठ, महंत सुन्दरदास महाराज, संत रसिक माधव दास, प्रमुख समाजसेवी एस. के. शर्मा, याज्ञिक रत्न आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, आचार्य मृदुलकांत शास्त्री, डॉ. मनोज मोहन शास्त्री, प्रख्यात चित्रकार ₹यूपी रत्न₹ द्वारिका आनंद, भागवताचार्य संजीव कृष्ण ठाकुरजी, महंत रामचंद्र दास, आचार्य पीठाधीश्वर स्वामी यदुनंदनाचार्य महाराज, सनातन पथ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर गौरव शर्मा, प्रख्यात सनातन सेवी अंशुल पाराशर, युवराज वेदांत आचार्य, युवा साहित्यकार डॉ. राधाकांत शर्मा, पार्षद सुमित गौतम, आचार्य ईश्वरचन्द्र रावत आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का समापन सन्त, ब्रजवासी वैष्णव सेवा एवं वृहद भंडारे के साथ हुआ।जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया।

किसी तरह से मिल जाएं गैस सिलेंडर

परिवहन विशेष न्यूज

गोरखपुर/चौरीचौरा। जिले में व ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे-धीरे गैस की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। गैस एजेंसियों पर लंबी-लंबी लाइन यह बताने के लिए पर्याप्त है कि गैस की किल्लत बढ़ती जा रही हैं। सुबह होते ही जहां लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगा रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार हैरान परेशान हों करते नजर आ रहे हैं। यहीं नहीं सबको उसी दिन गैस मिल पाना संभव भी नहीं है। पूरे दिन लोग गैस एजेंसियों के संचालकों का फोन मिलाते फिर रहे हैं की किसी तरह से गैस सिलेंडर मिल जाए। जिसका गैस खत्म है वह भी और जिसका गैस खत्म नहीं है हुआ है वह भी लाइनों में लगकर एक्स्ट्रा गैस प्राप्त करना चाह रहा है जिससे गैस एजेंसियों के सामने लाइन लंबी-लंबी लग रही हैं। लंबी लाइन लगने के एक और कारण बैकलाग पुरा न हो पाना भी है। एजेंसी संचालकों ने दबे जुबान माना है की मांग के अनुसार सिलेंडर नहीं आ रहा है जिस कारण से लाइन लंबी लग रही हैं। ऊपर के बड़े जिम्मेदार सिलेंडर पर्याप्त होने की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ उपभोक्ताओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि धांधली और कालाबाजारी भी हो रहा है। यहीं नहीं चर्चा यह भी है ब्लैक में एक सिलेंडर का ₹1500 सौ भी लिया जा रहा है। लोगों का मानना है की ओटीपी व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू हो जाने से हालात सुधर जाएं।

धुंध ने बढ़ाई किसानों की चिंता

परिवहन विशेष न्यूज

गोरखपुर। शनिवार से छाई धुंध मंगलवार को समाचार लिखे जाने तक छाई हुई थी। शनिवार रविवार को धुंध थोड़ी कम तो रही लेकिन सोमवार को दोनों दिनों की अपेक्षा ज्यादा रही। धुंध के छाए रहने से फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। गेहूं, सरसों और फूलों वाली फसलों पर माहों नाम के कीटों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। गेहूं की बालियों पर यह किट इस कदर छाए हुए हैं की बालियां काली पड़ रही हैं। यही हाल सरसों की फसलों की भी है। मालूम हो कि गेहूं की फसलों में अभी बालियां फूलों के साथ आई हैं। अगेती की फसलों में बालियां धीरे-धीरे पकाने के कगार पर हैं लेकिन पीछे बोई गई गेहूं की फसल को यह माहो किट बहुत प्रभावित कर रही हैं। गेहूं की बालियां ठीक से पक नहीं पाएंगी और दाने पतले हो जाएंगे। विष्णु, प्रदीप, रमेश, सतेंद्र, सतीश आदि किसानों ने बताया कि गेहूं की बालियां काली हो गई हैं। इससे गेहूं की बालियां प्रभावित होगी और पैदावार भी प्रभावित होगा। माहों कीट के प्रकोप को रोकने के लिए कुछ किसान दवाओं का छिड़काव भी शुरू कर दिए हैं। माहों किट के बढ़ते प्रभाव की वजह से और छाई धुंध की वजह से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम के जानकारों का मानना है कि जब तक कोई हवा नहीं चलेगी तब धुंध नहीं छटेगी और न किटों की संख्या कम होगी।

हिंदू महिलाओं को भी सुरक्षा के लिए हथियार लेकर चलना होगा - भंते संघप्रिय राहुल - मोदी ने हर क्षेत्र में महिलाओं को दिया आरक्षण- बघेल

- भारतीय बौद्ध संघ ने मनाया महिला सशक्तीकरण सम्मान समारोह

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारतीय बौद्ध संघ की ओर से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और महान समाज सुधारक, महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर मावलंकर हॉल में मंगलवार को सामाजिक समरसता महिला सशक्तीकरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते डॉ संघप्रिय राहुल ने महिलाओं के प्रति बढ़ते स्ट्रीट क्राइम और अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि जिस तरह सिख धर्म में महिलाओं को कृपाण लेकर चलने की अनुमति है, उसी प्रकार हिंदू महिलाओं व युवतियों को भी अपनी रक्षा के लिए हथियार लेकर चलना होगा। आए दिन सड़कों पर महिलाओं से छेड़खानी, छीनाझपटी, मारपीट हो रही है, उसे देखते हुए यह अब जरूरी हो गया है। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन, डेयरी व पंचायती राज मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए उन्होंने हर क्षेत्र में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रखा है। उन्होंने सवाल उठाया कि कई अस्पतालों व नर्सिंग होमों में लिखा देखने को मिलता है कि यहां भ्रूण जांच नहीं होती, मुझे वहीं शक पैदा होता है कि आखिर, यह लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? जबकि हमारे समाज में इस तरह की जांच की प्रथा ही नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जांच कराकर हम क्या साबित करना चाहते हैं?

कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्यसभा सांसद दिनेश चंद अनवाड़िया, पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष कपिल खन्ना, मध्य प्रदेश के सागर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद डॉक्टर लता वानखेड़, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लाकड़ा ने भी संबोधित किया। इनके अलावा भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ज्ञानचंद गौतम, राष्ट्रीय महामंत्री दिल्ली प्रदेश प्रभारी एडवोकेट सुरेश वर्मा, संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश बुलाकी, दिल्ली प्रदेश बौद्ध संघ के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार, संघ की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी झा, संघ के राष्ट्रीय महामंत्री कुलदीप कदल बुजू जी, संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मेहर सिंह और संघ की दिल्ली महिला मोर्चा की अध्यक्ष बबली राठौर भी उपस्थित रहीं। कायक्रम में गायक मनजीत मेहरा ने बाबा साहेब पर बने गीतों से उपस्थितजनों को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में दूर दराज से आई 21 महिलाओं को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया।

गांवों में बनेंगे युवा मंडल

परिवहन विशेष न्यूज

गोरखपुर। सरदारनगर विकास खंड में युवाओं को संगठित कर राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से युवा मंडल विकास अभियान को तेज किया गया है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी सरदारनगर श्याम लाल द्वारा सभी ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सचिवों को पत्र जारी कर ग्राम स्तर पर युवा मंडलों के गठन के निर्देश दिए गए हैं।

जारी पत्र के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 संकल्प के अंतर्गत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित मेरा युवा भारत पहल के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा चौरी-चौरा के विधायक के निर्देश पर यह अभियान पूरे क्षेत्र में चलाया जा रहा है।

पत्र में बताया गया है कि प्रदेश के सर्वोच्च युवा सम्मान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सम्मानित सचिन गौरी वर्मा के मार्गदर्शन में विधानसभा क्षेत्र चौरी-चौरा के गांव-गांव में युवाओं को संगठित कर युवा मंडलों का गठन कराया जा रहा है।

खंड विकास अधिकारी ने सभी ग्राम प्रधानों एवं सचिवों को निर्देशित किया है कि वे सचिन गौरी वर्मा के मार्गदर्शन में युवाओं को संगठित कर युवा मंडलों के गठन में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। साथ ही अधिक से अधिक युवाओं को मेरा युवा भारत पोर्टल से जोड़ने का भी कार्य करें, जिससे युवाओं में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक सहभागिता तथा सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता विकसित हो सके।

दिल्ली पुस्तकालय संघ का 88 वां स्थापना दिवस एवं वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न

विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के बिना अधूरे हैं :-प्रो. प्रेम सिंह

नईदिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय गांधी भवन में दिल्ली पुस्तकालय संघ का 88 वां स्थापना दिवस एवं वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ हुआ।डीएलए के अध्यक्ष,गांधी भवन के निदेशक एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रो. के.पी. सिंह ने सभी आगंतुक अतिथियों का परिचय कराया।अतिथियों का अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत एवं अभिनंदन किया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष प्रो. प्रेम सिंह जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रो. एस आर रंगनाथन जैसे व्यक्तित्वों की कर्मठता के कारण आज हम पुस्तकालय विज्ञान विभाग को जान पाए हैं। गणित के प्रोफेसर होने के बाद भी प्रो. रंगनाथन जी की पुस्तकालय विज्ञान विषय को लेकर जो निष्ठा थी उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के बिना अधूरे हैं।विश्वविद्यालय पुस्तकालयों से ही आगे बढ़ सकते है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के आरंभ के समय से 1960 के दशक तक की पुस्तकालय विज्ञान विभाग एवं पुस्तकालय की यात्रा का संस्मरण याद करते हुए उनको जीवंत किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से 1957 में दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय का निर्माण संभव हुआ। 41605 पुस्तकों से 3 लाख पुस्तकों के संकलन तक का ऐतिहासिक समय 1965 तक रहा।उन्होंने प्रो. एस.दासगुप्ता के योगदान का भी स्मरण किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुस्तकालय विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष,प्रो. आर.के भट्ट ने सभी का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा प्रो.के पी सिंह जैसे कर्मयोगी जीवन में बहुत कम मिलते हैं। स्व प्रेरणा से आगे बढ़ने की जिजीविषा,कर्मठता इनके व्यक्तित्व को अति विशेष बनाती है। प्रो. के पी सिंह दिल्ली पुस्तकालय संघ की आज की प्रगति के भी परिचायक हैं।कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय की डीन(अकादमिक गतिविधि) प्रो. के. रत्नावली ने अपने संबोधन में सबसे पहले डीएलए का आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रो.के.पी.सिंह की कर्मठता की प्रशंसा की। पुस्तकालय एक संस्थान के रूप में विकसित हों यही कामना है।उन्होंने दिल्ली पुस्तकालय संघ के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी प्रेषित कीं। तत्पश्चात दिल्ली पुस्तकालय संघ का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न हुआ।

इसमें प्रो. प्रेम सिंह को सर जॉन सर्जेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, श्री जयवीर सिंह को आउटस्टैंडिंग प्रमोशन एंबेसेडर अवार्ड, श्री ए के सलिया को संत वशिष्ठ आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड, डॉ. ऋतु वर्मा को प्रो.सी.पी. वशिष्ठ लाइब्रेरी इनोवेशन अवॉर्ड एवं डॉ. अशोक कुमार को प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ पुस्तकालय विज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट अकादमिक प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के अंत में डॉ.ज्ञानेंद्र सिंह ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्राध्यापक डॉ.पिंकी शर्मा ने किया। कार्यक्रम में कई संकाय प्रमुख, विभागध्यक्ष, महाविद्यालयों के प्राध्यापक गण,शोधार्थी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

भारत में बुजुर्ग माता-पिता से संबंधित कानूनी मुद्दे

● विजय गर्ग

माता-पिता के प्रति सम्मान और देखभाल लंबे समय से भारतीय समाज में महत्वपूर्ण मूल्य रहे हैं। परंपरागत रूप से, परिवार अपने बुजुर्ग सदस्यों की सहायता करने की जिम्मेदारी लेते थे। हालाँकि, शहरीकरण, बदलती जीवनशैली और एकल परिवार के उदय के कारण, आज कई बुजुर्ग माता-पिता उपेक्षा, वित्तीय असुरक्षा और भावनात्मक अलगाव का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों के कारण आधुनिक भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सुरक्षा का महत्व बढ़ गया है।

बुजुर्ग माता-पिता के लिए बढ़ती चुनौतियां

कई बुजुर्ग माता-पिता वित्तीय और भावनात्मक सहायता के लिए अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं। दुर्भाग्यवश, कुछ माता-पिता को अपने परिवार के सदस्यों के साथ उपेक्षा, परित्याग या यहां तक कि संपत्ति से संबंधित विवाद का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में, बच्चे भोजन, चिकित्सा देखभाल और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने से इनकार कर देते हैं।

जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और परिवार संरचनाओं में परिवर्तन के साथ, ऐसी समस्याओं का सामना करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ रही है। परिणामस्वरूप, उनके अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए कानूनी तंत्र पेश किए गए हैं।

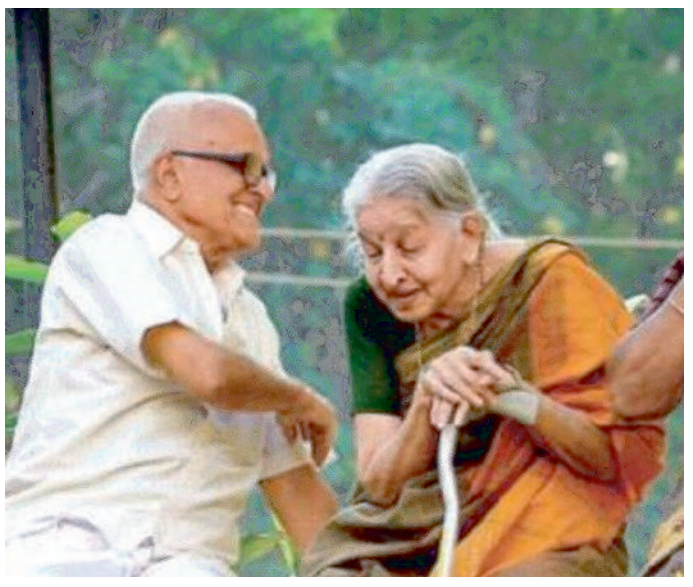

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सुरक्षा

इन चिंताओं को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 लागू किया। यह कानून बच्चों और उत्तराधिकारियों के लिए अपने बुजुर्ग माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करना कानूनी कर्तव्य बनाता है।

इस अधिनियम के तहत:

यदि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, तो वे अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से मासिक भरण-पूर्ति का दावा कर सकते हैं।

ऐसे मामलों के त्वरित समाधान के लिए विशेष रखरखाव न्यायाधिकरण स्थापित किए जाते हैं।

कानून में बुजुर्ग माता-पिता को संपत्ति पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, यदि वह बच्चों को हस्तांतरित कर दी गई हो, तो इस शर्त के साथ कि वे देखभाल प्रदान करेंगे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं करते।

इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिक गरिमा के साथ रहें और उन्हें वह सहायता मिले जिसके वे हकदार हैं।

संपत्ति और विरासत विवाद

संपत्ति संबंधी विवाद बुजुर्ग माता-पिता के सामने आने वाली सबसे आम कानूनी समस्याओं में से एक हैं। कुछ मामलों में, माता-पिता देखभाल और सहायता की अपेक्षा के साथ अपनी संपत्ति अपने बच्चों को हस्तांतरित कर देते हैं। जब बच्चे बाद में उनकी उपेक्षा करते हैं, तो माता-पिता को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

कानून ऐसी स्थितियों में उपाय प्रदान करता है। यदि संपत्ति देखभाल के वादे के तहत हस्तांतरित की गई थी, और बच्चे उस वादे को पूरा करने में विफल रहे, तो माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थानांतरण को अमान्य घोषित किया जा सकता है।

दुर्व्यवहार और उपेक्षा से सुरक्षा

वित्तीय उपेक्षा के अलावा, बुजुर्ग माता-पिता को भावनात्मक या शारीरिक दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ सकता है। भारतीय कानून ऐसे मुद्दों को मान्यता देता है और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी माध्यम से सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति देता है।

वे दुर्व्यवहार की सूचना देने के लिए रखरखाव न्यायाधिकरणों, स्थानीय प्राधिकारियों या पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। कई राज्यों ने संकटग्रस्त बुजुर्ग व्यक्तियों की सहायता के लिए वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन और सहायता सेवाएं भी शुरू कर दी हैं।

समाज और परिवार की भूमिका

यद्यपि कानून सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक समाधान पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक जागरूकता को मजबूत करने में निहित है। माता-पिता और बड़ों के प्रति सम्मान भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। परिवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुजुर्ग सदस्यों को देखभाल, साथ और सुरक्षा मिले।

समुदायों, सामाजिक संगठनों और सरकारों को भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत में कानूनी प्रावधानों का उद्देश्य बुजुर्ग माता-पिता को उपेक्षा से बचाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि वे गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीएं। हालाँकि, केवल कानून ही समस्या का समाधान नहीं कर सकते। एक दयालु समाज जो अपने बुजुर्गों को महत्व देता है, उतना ही आवश्यक है।

माता-पिता का ख्याल रखना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। बुजुर्ग माता-पिता का सम्मान और समर्थन करके, समाज कृतज्ञता, सहानुभूति और मानवता के मूल्यों को बनाए रख सकता है।

डॉ विजय गर्ग रिटायर्ड प्रिंसिपल
एजुकेशनल कॉलमिस्ट एमिनेंट
एजुकेशनिस्ट स्ट्रीट कौर चंद
एमएचआर मलोट पंजाब-152107

सादगी भरी शादियाँ: अमीर लोगों को समाज के लिए उदाहरण क्यों बनना चाहिए

(अमीरों की सादगी से बदलेगी शादी की सोच)

- डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक आयोजन भी माना जाता है। यहाँ शादी में परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और पूरा समाज शामिल होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शादियों का स्वरूप बहुत बदल गया है। आजकल कई शादियाँ इतनी भव्य और महंगी हो गई हैं कि उनमें करोड़ों रुपये तक खर्च किए जाते हैं। बड़े-बड़े होटल, महंगे कपड़े, विदेशी सजावट, मशहूर कलाकारों के कार्यक्रम और कई दिनों तक चलने वाले समारोह अब आम बात हो गए हैं।

ऐसी शादियों का सबसे बड़ा प्रभाव समाज के मध्यम और गरीब वर्ग पर पड़ता है। जब समाज में अमीर लोग बहुत महंगी शादियाँ करते हैं तो बाकी लोगों पर भी वैसी ही शादी करने का दबाव बनने लगता है। कई परिवार अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करने लगते हैं। कई बार तो लोग कर्ज लेकर शादी करते हैं ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। यही कारण है कि आज शादी कई परिवारों के लिए खुशी के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी बन जाती है।

ऐसे समय में समाज के बड़े और संपन्न लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अगर जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वे सादगी से शादी करें, तो यह पूरे समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। इससे यह संदेश जाएगा कि शादी की खुशी दिखावे या खर्च से नहीं बल्कि रिश्तों और संस्कारों से होती है।

इतिहास में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ बड़े और सम्मानित लोगों ने सादगी को महत्व दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की शादी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने दहेज लेने से साफ मना कर दिया था और केवल एक चरखा और कुछ कपड़े ही स्वीकार किए थे। उस समय भी समाज में दहेज और खर्च की परंपरा थी, लेकिन उन्होंने सादगी और सिद्धांतों को प्राथमिकता दी।

इसी तरह प्रसिद्ध उद्योगपति नारायण मूर्ति और समाजसेवी लेखिका सुधा मूर्ति की शादी भी बहुत साधारण तरीके से हुई थी। उस समय उनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं था, लेकिन बाद में जब वे बहुत सफल और संपन्न बने तब भी उन्होंने हमेशा सादगी और जिम्मेदारी का संदेश दिया। सुधा मूर्ति अक्सर कहती हैं कि शादी में फिजूल खर्च करने के बजाय पैसा शिक्षा और समाज सेवा में लगाया जाना चाहिए।

इसके विपरीत आधुनिक समय में कुछ शादियाँ इतनी भव्य हो गई हैं कि वे एक तरह से प्रदर्शन का माध्यम बन जाती हैं। उदाहरण के लिए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी। इसी तरह ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी भी बहुत बड़े स्तर पर आयोजित की गई थी। इन शादियों में कई बड़े उद्योगपति, अंतरराष्ट्रीय कलाकार और फिल्म सितारे शामिल हुए।

हालाँकि यह भी सच है कि जिन लोगों के पास पैसा है, वे अपनी खुशी के लिए खर्च करने का अधिकार रखते हैं। बड़ी शादियों से होटल उद्योग, सजावट, कैटरिंग, संगीत, फोटोग्राफी और कई अन्य क्षेत्रों में हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसलिए पूरी तरह से बड़ी शादियों की आलोचना करना भी उचित नहीं है।

फिर भी समाज के हित को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि बड़े और प्रभावशाली लोग संतुलन बनाए रखें। अगर वे सादगी और जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। जब लोग देखेंगे कि अमीर परिवार भी साधारण तरीके से शादी कर रहे हैं, तो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पर अनावश्यक खर्च करने का दबाव कम हो जाएगा।

आज भारत में कई युवा भी इस विषय पर नए विचार अपना रहे हैं। वे सादगी से शादी करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुछ लोग मंदिर में विवाह करते हैं, कुछ लोग कोर्ट मैरिज करते हैं और उसके बाद परिवार के साथ छोटा सा कार्यक्रम रखते हैं। इससे खर्च कम होता है और शादी का मूल उद्देश्य भी बना रहता है।

साधारण शादी के कई फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि परिवार को आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ता। कई बार शादी के खर्च के कारण परिवार वर्षों तक कर्ज में डूबे रहते हैं। अगर शादी सादगी से हो तो यह समस्या कम हो सकती है। दूसरा फायदा यह है कि पैसा बचाकर उसे किसी उपयोगी काम में लगाया जा सकता है, जैसे बच्चों की शिक्षा, घर की जरूरतें या समाज सेवा।

इसके अलावा सादगी से शादी करने से सामाजिक समानता का संदेश भी जाता है। समाज में अमीर और गरीब के बीच जो दिखावे की खाई बढ़ रही है, उसे कम करने में भी यह मददगार हो सकता है।

मीडिया और सोशल मीडिया का भी इस विषय में बड़ा प्रभाव है। आजकल शादी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी से फैलते हैं। जब लोग भव्य और महंगी शादियाँ देखते हैं तो उनके मन में भी वैसी ही शादी करने की इच्छा पैदा होती है। इसलिए जरूरी है कि सादगी भरी शादियों को भी उतना ही महत्व दिया जाए और उन्हें समाज में प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

सरकार और सामाजिक संस्थाएँ भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कई जगहों पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहाँ कम खर्च में कई जोड़ों की शादी करवाई जाती है। इससे गरीब परिवारों को बहुत राहत मिलती है और समाज में सादगी का संदेश भी फैलता है।

अंत में यह समझना जरूरी है कि शादी का असली अर्थ दिखावा नहीं बल्कि दो लोगों का साथ और दो परिवारों का मिलन है। खुशियाँ महंगे कपड़ों, बड़ी सजावट या भव्य कार्यक्रमों से नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और संस्कारों से बनती हैं।

इसलिए यदि समाज के बड़े और संपन्न लोग सादगी से शादी करके उदाहरण प्रस्तुत करें, तो यह पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। इससे न केवल अनावश्यक खर्च कम होगा बल्कि समाज में संतुलन, जिम्मेदारी और सादगी की भावना भी मजबूत होगी।

वास्तव में एक अच्छी शादी वही है जिसमें खुशी हो, सम्मान हो और परिवारों का स्नेह हो। अगर यह सब सादगी के साथ हो जाए, तो वही सबसे बड़ा उत्सव बन जाता है।

(डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक हैं।)

फॉलोअर्स की भूख और रिश्तों की नीलामी

- डॉ. सत्यवान सौरभ

डिजिटल युग ने अभिव्यक्ति के नए दरवाजे खोले हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी बात दुनिया तक पहुँचाने का अवसर दिया है। पहले जहां सूचना और मनोरंजन के साधन सीमित थे, वहीं आज कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन के जरिए वीडियो बना सकता है, ब्लॉग लिख सकता है और लाखों लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकता है। यह बदलाव लोकतांत्रिक भी है और प्रेरणादायक भी। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ नई चुनौतियाँ भी जन्म लेती हैं।

आज सोशल मीडिया की दुनिया में लोकप्रियता की एक नई परिभाषा बन चुकी है—फॉलोअर्स, लाइक्स, शेयर और व्यूज़। जितने ज्यादा ये आंकड़े होते हैं, उतना ही किसी व्यक्ति को सफल माना जाता है। इसी होड़ ने कई कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसी राह पर ला खड़ा किया है, जहां निजी जीवन की मर्यादाएं भी कंटेंट का हिस्सा बनती जा रही हैं।

बीते कुछ वर्षों में एक नया ट्रेंड तेजी से उभरा है—पारिवारिक झगड़ों और निजी विवादों को कैमरे के सामने लाकर सोशल मीडिया पर साझा करना। पति-पत्नी के विवाद, भाई-बहन के मतभेद, सास-बहू की तकरार या परिवार के अंदर की छोटी-छोटी बहसें—जो पहले घर की चारदीवारी में सुलझा ली जाती थीं—अब वीडियो और पोस्ट के रूप में लाखों दर्शकों के सामने परोसी जा रही हैं।

कई यूट्यूबर्स और ब्लॉगर इसे "रियल लाइफ कंटेंट" का नाम देते हैं। उनका तर्क होता है कि दर्शक वास्तविकता देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर वास्तविक घटना को सार्वजनिक करना जरूरी है? क्या निजी रिश्तों को दर्शकों की जिज्ञासा के लिए खोल देना उचित है?

असल में सोशल मीडिया का एल्गोरिथ्म भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। जिस कंटेंट में विवाद, भावनात्मक प्रतिक्रिया या सनसनी होती है, वह तेजी से वायरल होता है। लोग ऐसे वीडियो पर ज्यादा कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं और कभी-कभी पक्ष या विपक्ष में बहस भी करते हैं। यही कारण है कि कुछ क्रिएटर्स जानबूझकर ऐसे विषय चुनते हैं जो लोगों की भावनाओं को भड़का सकें।

दुर्भाग्य की बात यह है कि कई बार ये झगड़े वास्तविक होते हैं और परिवार के सदस्यों की निजता दांव पर लग जाती है। एक छोटी सी तकरार को कैमरे के सामने लाकर बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। इससे न केवल रिश्तों की गरिमा प्रभावित होती है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों—विशेषकर बच्चों—पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है।

कुछ मामलों में तो यह भी देखने में आया है कि विवादों को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है या फिर पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होता है। यानी झगड़ा असली नहीं होता, लेकिन उसे असली दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि दर्शकों का ध्यान खींचा जा सके। यह स्थिति मनोरंजन और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है।

सोशल मीडिया के इस दौर में "वायरल" होना ही सफलता का पर्याय बन गया है। जब किसी वीडियो को लाखों व्यूज़ मिलते हैं और हजारों नए फॉलोअर्स जुड़ते हैं, तो क्रिएटर को लगता है कि उसने सही रास्ता चुना है। लेकिन यह लोकप्रियता अक्सर क्षणिक होती है। जिस विवाद ने एक दिन दर्शकों का ध्यान खींचा, वही अगले दिन किसी और नए विवाद से दब जाता है।

इस प्रवृत्ति का एक सामाजिक पहलू भी है। जब दर्शक बार-बार ऐसे कंटेंट देखते हैं, तो धीरे-धीरे उन्हें यह सामान्य लगने लगता है कि निजी रिश्तों को सार्वजनिक मंच पर लाकर चर्चा का विषय बनाया जाए। इससे समाज में गोपनीयता और मर्यादा की भावना कमजोर पड़ सकती है।

हमारे समाज में परिवार को हमेशा एक मजबूत संस्था माना गया है। परिवार केवल साथ रहने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा, विश्वास और आपसी समझ का आधार भी है। जब परिवार के अंदर की समस्याओं को सार्वजनिक तमाशा बना दिया जाता है, तो यह उस भरोसे को कमजोर करता है जो रिश्तों की नींव होता है।

इसके अलावा, सोशल मीडिया पर आने वाले दर्शकों में बड़ी संख्या युवा और किशोरों की भी होती है। वे जो कुछ देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। अगर वे बार-बार यह देखेंगे कि लोकप्रियता पाने के लिए निजी विवादों को सार्वजनिक करना सामान्य बात है, तो उनके मन में भी यही धारणा बन सकती है कि जीवन में सफलता के लिए किसी भी हद तक जाना स्वीकार्य है।

यह भी सच है कि सभी कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे नहीं होते। बहुत से यूट्यूबर्स, ब्लॉगर और डिजिटल क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो ज्ञानवर्धक, रचनात्मक और सकारात्मक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृति, यात्रा और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले अनेक लोग सोशल मीडिया को एक सकारात्मक मंच के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके प्रयास यह साबित करते हैं कि लोकप्रियता पाने के लिए विवाद और ड्रामा ही एकमात्र रास्ता नहीं है।

असल सवाल जिम्मेदारी का है। जब किसी के पास हजारों या लाखों लोगों तक पहुंचने की ताकत होती है, तो उसके साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। कंटेंट क्रिएटर्स को यह समझना चाहिए कि उनकी सामग्री केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि लोगों की सोच और दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है।

दर्शकों की भी इसमें भूमिका कम नहीं है। आखिर वही तय करते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट ज्यादा देखा जाएगा और किसे नजरअंदाज किया जाएगा। अगर दर्शक केवल सनसनी और विवाद वाले वीडियो को ही बढ़ावा देंगे, तो स्वाभाविक है कि ऐसे कंटेंट की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर वे रचनात्मक और सकारात्मक सामग्री को अधिक समर्थन देंगे, तो डिजिटल दुनिया का माहौल भी बदल सकता है।

आज जरूरत इस बात की है कि सोशल मीडिया के उपयोग में संतुलन और समझदारी लाई जाए। निजी जीवन की सीमाएं तय की जाएं और यह समझा जाए कि हर घटना को सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं होता। लोकप्रियता और फॉलोअर्स का महत्व अपनी जगह है, लेकिन रिश्तों की गरिमा और व्यक्तिगत सम्मान उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।

युद्ध की विभीषिका: हारती मानवता और सिसकता विश्व।

सुनील कुमार महला

युद्ध वास्तव में केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसका सबसे गहरा घाव मानवता की आत्मा पर लगता है। कहना गलत नहीं होगा कि आज का विश्व एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ प्रगति की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन धरातल पर विनाश की पदचाप साफ़ सुनाई देती है। पिछले कुछ समय से अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को अनिश्चितता के भंवर में धकेल दिया है। सच तो यह है कि इस संघर्ष के कारण चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और तबाही का मंजर करीब आता दिखाई दे रहा है। यह संघर्ष केवल दो-तीन देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, मानवीय संवेदनाओं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी पड़ रहा है।

युद्ध और आर्थिक तबाही:-

यह एक कड़वा सच है कि युद्ध का सबसे पहला और प्रत्यक्ष प्रहार आम आदमी की जेब और पेट पर होता है। मध्य-पूर्व दुनिया के तेल और गैस का प्रमुख केंद्र है। जब भी यहाँ युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) बाधित हो जाती है। तेल और गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि महंगाई को चरम पर पहुँचा देती है। एक गरीब परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि युद्ध के कारण परिवहन और उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। यह आर्थिक संकट केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे विश्व के लिए साझा संकट बन जाता है।

अहम और विस्तारवाद की अंधी दौड़:-

युद्ध कभी भी अचानक नहीं होते; इनके पीछे लंबे समय से पल रही कुंठाएँ, विस्तारवादी नीतियाँ और शासकों की मनमानी होती है। जब देशों के बीच संवाद समाप्त हो जाता है और 'अहम' (इगो) बड़ा हो जाता है, तब कूटनीति के रास्ते बंद हो जाते हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज परमाणु हथियारों की होड़ ने मानव जाति को विनाश के उस मुहाने पर खड़ा कर दिया है जहाँ एक छोटी-सी गलती पूरी सभ्यता को मिटा सकती है। धार्मिक कट्टरवाद, जातीय संघर्ष और सीमा विवाद जैसे मुद्दे आग में घी डालने का काम करते हैं। जब शासक अपनी शक्ति के प्रदर्शन में अंधे हो जाते हैं, तो वे यह भूल जाते हैं कि जिस धरती को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उसे रहने लायक भी नहीं छोड़ेंगे।

युद्ध: इंसानियत की हार:-

इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं रहे। युद्ध केवल नए युद्धों का बीज बोते हैं। किसी भी संघर्ष में न कोई देश वास्तव में जीतता है और न ही कोई हारता है; अगर कुछ हारता है तो वह है मानवता।

सच तो यह है कि युद्ध के मैदान में बारूद की गंध के बीच सबसे पहले करुणा और दया की बलि चढ़ती है। जब बम गिरते हैं, तो वे यह नहीं देखते कि नीचे कौन है। मलबे के ढेर पर बैठकर बिलखते बच्चे, अपनों को खो चुकी महिलाएँ और बेबस बुजुर्ग इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि युद्ध कितना क्रूर होता है। जो बच्चे आज खिलौनों से खेलना चाहते हैं, उनके हाथों में युद्ध ने नफरत और विनाश की यादें थमा दी हैं। जिस देश को बनाने में दशकों का पसीना और मेहनत लगती है, युद्ध उसे कुछ ही दिनों में खंडहर बना देता है और देश बरसों पीछे चला जाता है।

युद्धग्रस्त देशों की भयावह स्थिति:-

यह विचारणीय है कि दुनिया के कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने युद्धरत देशों से युद्धविराम की अपील की है, लेकिन शासकों की जिद के कारण दुनिया असहाय दिखाई दे रही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसकी प्रासंगिकता को लेकर बहस तेज हो गई है। दूसरी ओर युद्धग्रस्त देशों की स्थिति बेहद भयावह है। लगातार बमबारी के कारण बड़े-बड़े शहर खंडहर में बदल चुके हैं। सड़कों पर जगह-जगह लाशें बिखरी पड़ी हैं और अस्पतालों में घायल मासूम बच्चों की दर्दनाक तस्वीरें दिल दहला देती हैं। चारों ओर आग और धुएँ का वातावरण है। एंबुलेंस और हवाई हमलों के सायरन हर पल खामोशी को चीरते रहते हैं। अस्पतालों, स्कूलों, थिएटरों और रिहायशी इलाकों पर बमबारी के बाद जान बचाने के लिए सड़कों पर भागती भीड़ का दृश्य अत्यंत पीड़ादायक है। पानी, दूध, ब्रेड और दवाइयों के लिए परेशान महिलाओं और बुजुर्गों की भीड़ मानवता को शर्मसार करती है और युद्धरत देशों के शासकों की संवेदनहीनता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

शरणार्थियों की त्रासदी:-

इतिहास यह भी बताता है कि युद्ध में किसी की वास्तविक जीत नहीं होती, बल्कि हार हमेशा मानवता की होती है। विश्व युद्धों से लेकर विभिन्न देशों के बीच हुए संघर्षों ने यह सिद्ध किया है कि युद्ध की भयावहता का प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक बना रहता है।इन युद्धों में उन निर्दोष युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की जान जाती है, जिनका इस लड़ाई की जीत या हार से कोई संबंध नहीं होता। युद्ध के कारण शरणार्थियों की समस्या भी पैदा होती है। लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। वहाँ उनका जीवन अक्सर दोयम दर्जे के नागरिक जैसा हो जाता है और उन्हें रोटी, कपड़ा तथा सिर पर छत के लिए भी प्रशासन की मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। शरणार्थियों की यह समस्या कई देशों के लिए आर्थिक बोझ भी बनती है और कई बार सामाजिक तनाव का कारण भी बन जाती है।

निष्कर्ष:-

अंत में यही कहूंगा कि युद्ध विकास का अंत और विनाश का प्रारंभ है। नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार, संसाधनों पर कब्जे की होड़ और धार्मिक कट्टरता-ये सभी समाज को खोखला करने वाले तत्व हैं, जो अंततः युद्ध का रूप ले लेते हैं।आज समय की मांग है कि विश्व के नेतृत्वकर्ता अपने निजी स्वार्थों और झूठी शान को त्यागकर शांति के मार्ग पर चलें। हमें यह समझना होगा कि धरती पर संसाधनों की कमी नहीं है; कमी है तो केवल इंसानियत और आपसी समझ की। यदि आज हम नहीं संभले, तो आने वाली पीढ़ियों के पास इतिहास पढ़ने के लिए पन्ने तो होंगे, लेकिन रहने के लिए सुरक्षित दुनिया नहीं होगी। अंततः यही कहा जा सकता है कि शांति ही एकमात्र विकल्प है। दुनिया के शासकों को इतिहास से सबक लेने की आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं करता; यह केवल विनाश और पीड़ा ही लाता है। आज के वैश्विक माहौल में दुनिया को युद्ध नहीं, बल्कि अहिंसा और शांति के उस मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है जिसे गौतम बुद्ध और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने मानवता के लिए दिखाया था। वास्तव में तभी मानवता की रक्षा संभव है।

फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति- मुख्यमंत्री टकराव- क्या यह संवैधानिक गरिमा का प्रश्न है या चुनावी राजनीति की रणनीति?- चुनावी राजनीति, संवैधानिक संस्थाओं और संघीय ढांचे के बीच संतुलन बनाए रखना ज़रूरी -समग्र विश्लेषण

लोकतंत्र में प्रोटोकॉल केवल औपचारिक नियम नहीं होते बल्कि वे संस्थाओं की गरिमा और व्यवस्था को बनाए रखने का माध्यम होते हैं चुनावी मौसम और संवैधानिक टकराव का नया अध्याय – राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संवैधानिक मर्यादाओं और संस्थाओं का सम्मान करना लोकतंत्र की मज़बूती का सटीक मंत्र – एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं की गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है,जहाँ संवैधानिक मर्यादाएँ, प्रोटोकॉल,राजनीति और चुनावी रणनीतियाँ एक साथ टकराती नज़र आती हैं। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी बीच राष्ट्रपति के उत्तर बंगाल दौरे को लेकर पैदा हुआ विवाद राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। इस विवाद के केंद्र में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच राजनीतिक टकराव भी दिखाई देता है। एक ओर केंद्र सरकार और सत्तारुढ़ पार्टी इसे राष्ट्रपति पद की गरिमा और संविधान के सम्मान से जोड़कर देख रही है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की सीएम इसे चुनाव से पहले की राजनीतिक रणनीति और केंद्र द्वारा राज्य सरकार को घेरने की कोशिश बता रही हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि यह विवाद केवल प्रोटोकॉल या औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह केंद्र-राज्य संबंधों, संवैधानिक मर्यादाओं और चुनावी राजनीति की जटिलताओं को भी उजागर कर रहा है।लोकतंत्र में प्रोटोकॉल केवल औपचारिक नियम नहीं होते बल्कि वे संस्थाओं की गरिमा और व्यवस्था को बनाए रखने का माध्यम होते हैं।राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या अन्य संवैधानिक पदों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल इसलिए बनाए गए हैं ताकि शासन प्रणाली में अनुशासन और सम्मान बना रहे। यदि इनका पालन नहीं होता तो इससे संस्थागत असंतुलन पैदा हो सकता है।आने वाले महीनों में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा होने की संभावना है। ऐसे में यह विवाद चुनावी प्रचार का प्रमुख मुद्दा बन सकता है।सत्ताधारी पार्टी इसे संवैधानिक सम्मान और आदिवासी गौरव के मुद्दे के रूप में प्रस्तुत कर सकती है, जबकि पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी इसे केंद्र की राजनीतिक साजिश बताकर अपने समर्थकों को लामबंद करने की कोशिश करेगी। इस पूरे विवाद में मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। विभिन्न समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इस घटना को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है,कुछ लोग इसे राष्ट्रपति का अपमान मान रहे हैं,जबकि कुछ इसे राजनीतिक विवाद बता रहे हैं।लोकतंत्र में मीडिया जनमत को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और ऐसे मामलों में उसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

साथियों बात अगर हम राष्ट्रपति का उत्तर बंगाल दौरा और विवाद की शुरुआत को समझने की करें तो,पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब माननीय राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित नौवें अंतरराष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुँचीं। यह कार्यक्रम एक निजी संगठन इंटरनेशनल संथाल काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया था।मूल रूप से इस सम्मेलन का आयोजन दार्जिलिंग जिले के बिधाननगर क्षेत्र में प्रस्तावित था, जहाँ बड़ी संख्या में संथाल आदिवासी समुदाय के लोगों के पहुँचने की संभावना थी। हालांकि बाद में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और अन्य प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए कार्यक्रम स्थल को बदलकर बागडोगरा एयरपोर्ट के पासगोशाईंपुर कर दिया गया।राष्ट्रपति ने स्वयं इस परिवर्तन परअसंतोष व्यक्त किया और कहा कि नया स्थल छोटा था,जिसके कारण हजारों संथाल समुदाय के लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। राष्ट्रपति की यह नाराजगी धीरे-धीरे राजनीतिक विवाद का रूप लेने लगी।

साथियों बात अगर हम प्रोटोकॉल का प्रश्न और राष्ट्रपति की नाराजगी को समझने की करें तो राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि उनके स्वागत के लिए न तो मुख्यमंत्री और न ही राज्य सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री उपस्थित था।उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को छोटी बहन बताते हुए यह सवाल भी किया कि क्या वे उनसे नाराज हैं?। राष्ट्रपति के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से प्रोटोकॉल के पालन पर प्रश्न उठाया। इस बयान के बाद सत्तारुढ़ पार्टी ने इसे संवैधानिक गरिमा से जोड़कर मुद्दा बनाया और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

साथियों बात अगर हम प्रधानमंत्री और सत्ताधारी पार्टी की प्रतिक्रिया को समझने की करें तो पीएम ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह केवल राष्ट्रपति का अपमान नहीं बल्कि भारत के संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि द्रौपदी मुर्मू स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं और उनके विकास के लिए समर्पित हैं, ऐसे में उनके कार्यक्रम में अव्यवस्था होना और राज्य सरकार का उचित सहयोग न मिलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा नेताओं ने इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया। सत्तारुढ़ पार्टी के लिए यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण था क्योंकि बंगाल में आदिवासी समुदाय एक महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है।

साथियों बात अगर हम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कापलटवार और राजनीतिक आरोप को समझने की करें तो उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे सेखारिज करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम राज्य सरकार का नहीं बल्कि एक निजी संस्था का आयोजन था।उनके अनुसार राज्य प्रशासन ने पहले ही राष्ट्रपति सचिवालय को यह सूचित कर दिया था कि आयोजकों की तैयारी पर्याप्त नहीं है और इतनी बड़ी सभा को संभालने की क्षमता उनके पास नहीं है।उन्होंने यह भी कहा कि यदि राष्ट्रपति साल में एक बार किसी कार्यक्रम में आती हैं तो वे स्वयं स्वागत केलिए जा सकती हैं,लेकिन यदि चुनाव से पहले बार-बार कार्यक्रम होते हैं तो हर बार उपस्थित रहना संभव नहीं है। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के पद का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी का यह बयान राजनीतिक दृष्टि से बेहद तीखा माना गया क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राष्ट्रपति सत्ताधारी पार्टी की नीतियों और निर्देशों से प्रभावित होकर कार्य कर रही हैं।

साथियों बात अगर हम इस मुद्दे को केंद्र–राज्य टकराव का नया आयाम इस दृष्टिकोण से समझने की करें तो यह विवाद धीरे-धीरे केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव का रूप लेने लगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और पूछा कि मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक राष्ट्रपति के स्वागत के लिए क्यों उपस्थित नहीं थे। साथ ही यह भी पूछा गया कि कार्यक्रम स्थल और मार्ग की व्यवस्था ब्लू बुक के अनुसार क्यों नहीं की गई। इन सवालों ने इस मामले को केवल राजनीतिक बहस से आगे बढ़ाकर प्रशासनिक और संवैधानिक जांच के दायरे में ला दिया।

> साथियों बात अगर हम प्रधानमंत्री और सत्ताधारी पार्टी की प्रतिक्रिया को समझने की करें तो पीएम ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह केवल राष्ट्रपति का अपमान नहीं बल्कि भारत के संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि द्रौपदी मुर्मू स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं और उनके विकास के लिए समर्पित हैं, ऐसे में उनके कार्यक्रम में अव्यवस्था होना और राज्य सरकार का उचित सहयोग न मिलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

साथियों बात अगर हम ब्लू बुक क्या है और इसकामहत्व क्या है इसको समझने की करें तो,इस विवाद के बाद सबसे अधिक चर्चा जिस शब्द की हुई वह था ब्लू बुक। भारत में जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा, स्वागत और अन्य व्यवस्थाएँ गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक विशेष प्रोटोकॉल दस्तावेज़ के अनुसार होती हैं जिसे ब्लू बुक कहा जाता है। यह दस्तावेज़ अत्यंत गोपनीय होता है और केवल चुनिंदा अधिकारियों को ही उपलब्ध कराया जाता है। इसमें राष्ट्रपति के आगमन से लेकर कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था, सुरक्षा, मार्ग, झंडा, राष्ट्रगान, बैठने की व्यवस्था और आपातकालीन योजनाओं तक हर छोटी- बड़ी बात का विस्तृत विवरण होता है।ब्लू बुक के प्रमुख प्रावधान- ब्लू बुक के अनुसार जब राष्ट्रपति किसी राज्य में पहुँचते हैं तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित मंत्री को हवाईअड्डे पर स्वागत के लिए उपस्थित रहना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकते तो मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के लिए तय मार्ग पूरी तरह साफ- सुथरा होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक- चौबंद होनी चाहिए और कार्यक्रम स्थल पर सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। यह केवल औपचारिकता नहीं बल्कि राष्ट्र की गरिमा और संवैधानिक शिष्टाचार का हिस्सा माना जाता है।पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में कहा कि कार्यक्रम पूरी तरह एक निजी संगठन द्वारा आयोजित था और राज्य सरकार की भूमिका सीमित थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रशासन ने पहले ही आयोजकों की तैयारियों को लेकर चिंता व्यक्त की थी और राष्ट्रपति सचिवालय को इस बारे में सूचित कर दिया गया था। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति प्रशासनिक कारणों से थी और प्रोटोकॉल का कोई जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया।

साथियों बात अगर हम इसका राजनीतिक विश्लेषणः चुनावी रणनीति या संवैधानिक मुद्दा को समझने की करें तो, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव निकट हैं। सत्ताधारी पार्टी लंबे समय से बंगाल में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और आदिवासी समुदाय को अपने पक्ष में लाने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी भी इस समुदाय में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर उठा विवाद चुनावी राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है।

साथियों बात अगर हम संवैधानिक गरिमा और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को समझने की करें तो यह घटना एक बड़े प्रश्न को भी जन्म देती है कि क्या संवैधानिक पदों को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से अलग रखा जा सकता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना गया है और उनका पद दलगत राजनीति से ऊपर माना जाता है। लेकिन जब राजनीतिक दल इस प्रकार के विवादों को चुनावी मुद्दों में बदल देते हैं तो इससे संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी प्रश्न उठने लगते हैं।यह विवाद भारत के संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के संबंधों पर भी प्रकाश डालता है। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था पर आधारित है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की अपनी- अपनी शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन जब राजनीतिक मतभेद बढ़ जाते हैं तो प्रशासनिक और संवैधानिक मुद्दे भी टकराव का कारण बन जाते हैं। पश्चिम बंगाल का यह मामला इसी प्रवृत्ति का उदाहरण माना जा रहा है। आदिवासी राजनीति का आयाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और उनका राजनीतिक-सामाजिक महत्व भी अत्यंत बड़ा है। इसलिए इस विवाद को आदिवासी अस्मिता से जोड़कर देखा जाना भी स्वाभाविक है। भाजपा इस मुद्दे को आदिवासी सम्मान के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बता रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी राजनीति भी बंगाल चुनाव में एक महत्वपूर्ण कारक बनने जा रही है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक संतुलन की आवश्यकता जरूरी है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर उत्पन्न हुआ विवाद केवल एक प्रोटोकॉल विवाद नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के कई आयामों को उजागर करता है। यह घटना दिखाती है कि चुनावी राजनीति, संवैधानिक संस्थाओं और संघीय ढांचे के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संवैधानिक मर्यादाओं और संस्थाओं का सम्मान बना रहे। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह विवाद किस दिशा में जाता है, क्या यह केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा या इससे भविष्य में प्रोटोकॉल और केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर कोई नई व्यवस्था विकसित होगी।

आखिर तेल के वैश्विक खेल से कैसे और कब तक निबटेगा भारत?

कमलेश पांडेय

अमेरिका की ब्रितानी साम्राज्यवादी चाहत से विकासशील दुनिया एक बार फिर संकट में फंस चुकी है। पहले कुवैत-इराक युद्ध के बहाने और अब इजरायल-ईरान युद्ध की आड़ लेकर अमेरिका ने जो युद्ध और तेल का खेल किया, उससे अमेरिकी कम्पनियां तो मालामाल हुईं लेकिन इससे अभिशप्त विकासशील देश तबाह!

वैसे तो पश्चिम और मध्य-पूर्व एशियाई देशों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा पैदा करके अमेरिका अपनी और अपने डॉलर की बादशाहत बनाए रखता है, और जब भी उसकी नीति को इराक, ईरान जैसे मजबूत देशों से चुनौती मिलती है तो उन्हें वह बर्बाद कर देने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ता।

देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ड्रग्स स्मगलिंग और नानाविध उकसाऊ लोकतांत्रिक संगठन, जो धर्म और क्षेत्र के नाम पर लक्षित जगहों पर उन्माद पैदा करते आये हैं, वे सब उसके ही तो घिनौने चेहरे हैं, जिससे दुनिया अब वाकिफ हो चुकी है।

उधर, जब अमेरिकी खलनीति पर पलटवार स्वरूप रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और भारत की दिलचस्पी भी अरब और खाड़ी के देशों में बढ़ी तो उसने तुर्किये, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे खलीफे मजबूत किए जो दोनों तरफ खेलने लगे। इससे अमेरिका के समर्थकों की भी परेशानी बढ़ी।

इसी सामरिक होड़ में अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसने हथियाना चाहा। लेकिन लोगों को शांति नहीं, उलझने मिलीं। डरपोक चीन, कायर रूस और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले भारत ने अपनी अस्पष्ट नीतियों से पश्चिम-मध्यपूर्व एशिया को युद्ध का मैदान तो बनवा दिए, लेकिन जब खुद लड़ने की बारी आई, तो ईरान को अकेले शहीद होने के लिये छोड़ दिए। न ब्रिक्स उसके काम आया, न इस्लामिक नाटो! क्या यही रणनीतिक स्वायत्तता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खुले उल्लंघन पर भी जश्न मनाती है या खामोश हो जाती है।

सच कहूं तो आतंकवाद इसी वैश्विक चौधराहट की उर्वर फसल है जिसे कसाई प्रवृत्ति वाले अनपढ़ मुसलमानों ने खूब अपनाया और अल्लाह के नाम पर कठमुल्लों ने इससे खूब कमाया। लिहाजा मानवता विरोधी इस्लामिक आतंकवाद को शह देने की कीमत अमेरिका-यूरोप और अरब-खाड़ी देशों को आज नहीं तो कल चुकाना ही था, लेकिन उनके चक्कर में जो ऊर्जा व्यापार तबाह हुआ, उसकी भारी कीमत अब भारत जैसे मजबूत तेल-गैस उपभोक्ता चुकाएंगे।

यही वजह है कि वैश्विक तेल संकट से निपटने के लिए भारत अब आयात विविधीकरण, रणनीतिक भंडारण विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर काफी मजबूत रणनीति अपना रहा है। फिलवक्त मिडिल ईस्ट तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता कम करने पर जोर है। जहां तक वर्तमान चुनौतियों की बात है तो पश्चिम एशिया में ईरान-सऊदी संघर्ष से तेल आपूर्ति बाधित हो रही है, जहाँ भारत का 50-60% कच्चा तेल होर्मुज से गुजरता है। चूंकि कच्चे तेल के दाम 10 प्रतिशत से अधिक चढ़ चुके हैं, जो महंगाई बढ़ा सकता है। भारत 87% तेल आयात पर निर्भर है।

जहां तक आयात विविधीकरण की बात है तो भारत अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और रूस से अतिरिक्त तेल खरीद बढ़ा रहा है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीददारी पर 30-दिन की छूट दी है, जबकि ओपेक (OPEC) का हिस्सा 53% तक पहुँच गया। अब 40 देशों से आयात हो रहा है।

जहां तक रणनीतिक भंडार की बात है तो भारत के पास 250 मिलियन बैरल से अधिक तेल भंडार हैं, जो 7-8 सप्ताह (या 50 दिन) तक चल सकते हैं। वहीं नए भंडार बीकानेर, मंगलुरु, बीना में बन रहे हैं, जो 90-दिन लक्ष्य की ओर मजबूत पांव बढ़ाएंगे।

जहां तक दीर्घकालिक उपाय की बात है तो इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% पहुँच चुका, जो 44 मिलियन बैरल तेल बचाता है। वहीं EV इंफ्रास्ट्रक्चर, CBG, बायोडीजल और गैस को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही विदेशी तेल संपत्तियों का विस्तार करना भी योजना में है।

सवाल है कि ईरान-इजरायल युद्ध, और इससे पहले यूक्रेन-रूस युद्ध का इस तेल के खेल पर कितना असर महसूस हुआ तो जवाब होगा कि ईरान-इजरायल युद्ध ने भारत पर तेल आपूर्ति बाधा व कीमत वृद्धि के रूप में तत्काल प्रभाव डाला है, जबकि यूक्रेन-रूस युद्ध ने सस्ते रूसी तेल की उपलब्धता से लाभ पहुँचाया। दोनों ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित किया।

जहां तक ईरान-इजरायल युद्ध के असर की बात है तो फरवरी 2026 से शुरू हुए इस संघर्ष ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर खतरा बढ़ाया, जहाँ से भारत का 90% तेल आयात होता है। इससे तेल कीमतें 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गईं, जिससे पेट्रोल-डीजल महंगे हुए, शेयर बाजार दबाव में आये व महंगाई बढ़ी। इससे कृषि निर्यात जैसे बासमती चावल-चाय भी प्रभावित हो सकते हैं।

जहां तक यूक्रेन-रूस युद्ध के असर की बात है तो 2022 से रूस ने यूरोप खोने पर भारत को डिस्काउंट पर तेल बेचा, जिससे भारत ने 144 अरब यूरो (लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये) का तेल आयात किया। इससे आयात 13 गुना बढ़ा, जिसपर औसत 9-14% डिस्काउंट मिला, जो CAD व महंगाई बचाने में मददगार रहा। वहीं रूस अब भारत का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है जिससे भी अमेरिका को जलन हो चुकी है।

यही वजह है कि भारत ने तेल संकट से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं। भारत ने ईरान-इजरायल युद्ध से उत्पन्न तेल संकट से निपटने के लिए तत्काल कदम जैसे निर्यात प्रतिबंध, आयात विविधीकरण व मांग प्रबंधन उठाए हैं। ये उपाय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

जहां तक आपातकालीन उपाय की बात है तो पेट्रोल (1/3 निर्यात) व डीजल (1/4 निर्यात) के निर्यात पर रोक लगाने की योजना है जबकि एलपीजी (LPG) राशनिंग पर विचार किया गया है, क्योंकि 85-90% गैस गल्फ से आता है व स्टॉक 2 सप्ताह से कम है। वहीं पेट्रोल-डीजल दाम फिलहाल स्थिर रखे।

समानता और शिक्षा की क्रांतिकारी मशाल: सावित्रीबाई फुले

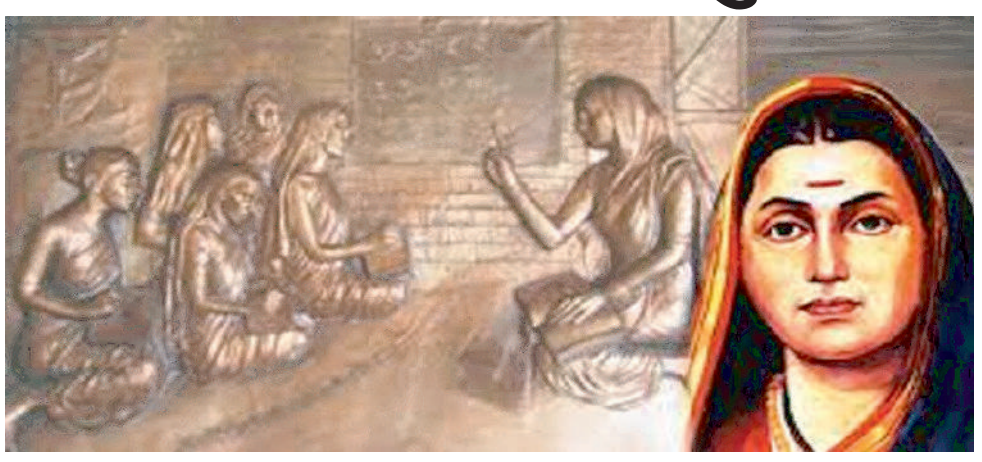

बाबूलाल नागा

भारतीय समाज में जब भी शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय की बात उठती है तो एक नाम इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है— सावित्रीबाई फुले। 10 मार्च को उनका महापरिनिर्वाण दिवस केवल श्रद्धांजलि देने का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन उस सामाजिक चेतना को याद करने का अवसर है, जिसने सदियों से जकड़े भारतीय समाज को झकझोरने का साहस किया।

19वीं सदी का भारतीय समाज गहरे अंधविश्वास, जातिगत ऊंच-नीच और महिलाओं के प्रति भेदभाव से ग्रस्त था। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था और समाज ने उनके लिए घर की चारदीवारी से बाहर निकलने के रास्ते लगभग बंद कर दिए थे। ऐसे दौर में सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन को सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में झोंक दिया। उनके साथ इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले।

सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय शुरू किया। यह केवल एक स्कूल की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ खुला विद्रोह था, जो मानती थी कि महिलाओं के लिए शिक्षा अनावश्यक है। जब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए घर से निकलती थीं, तो रास्ते में कट्टरपंथी लोग उन पर पत्थर, कीचड़ और गोबर तक फेंकते थे लेकिन वे न तो डरीं और न ही रुकीं। वे अतिरिक्त साड़ी साथ लेकर निकलती थीं, ताकि स्कूल पहुंचकर बदल सकें और बच्चियों को पढ़ाने का अपना संकल्प पूरा कर सकें। यह केवल साहस नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का बीज था। सावित्रीबाई फुले का स्पष्ट विश्वास था कि शिक्षा ही वह हथियार है, जो समाज में फैले अज्ञान, भेदभाव और अन्याय को समाप्त कर सकता है। उन्होंने लड़कियों के साथ-साथ दलितों और वंचित वर्गों को भी शिक्षा से जोड़ने का अभियान चलाया। उस समय जब जातिगत भेदभाव समाज की गहरी जड़ों में समाया हुआ था, तब उन्होंने शिक्षा को समानता का माध्यम बनाया और समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए भी ज्ञान के द्वार खोलने का प्रयास किया।

सावित्रीबाई फुले का संघर्ष केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने बाल विवाह, विधवाओं के शोषण और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भी मुखर आवाज उठाई। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय गृह शुरू किए और अनचाहे गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था की। उस दौर में यह पहल केवल सामाजिक सुधार नहीं थी बल्कि मानवता के पक्ष में खड़ा होने का साहसिक निर्णय था।

वे एक संवेदनशील कवयित्री और लेखिका भी थीं। उनकी रचनाओं में शिक्षा, आत्मसम्मान और सामाजिक बराबरी की स्पष्ट पुकार सुनाई देती है। उनके शब्द केवल साहित्य नहीं थे बल्कि समाज को जगाने वाली चेतावनी थे।

साल 1897 में पुणे में प्लेग की भयानक महामारी फैली। जब लोग संक्रमितों से दूरी बना रहे थे, तब सावित्रीबाई फुले बीमारों की सेवा में दिन-रात लगी रहीं। वे पीड़ितों को अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाती थीं। इसी सेवा के दौरान वे स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। उनका जीवन और उनका बलिदान मानवता की सेवा का अद्वितीय उदाहरण है।

आज जब हम सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं, तो यह सवाल भी हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या हम उनके सपनों का समाज बना पाए हैं? आज भी महिलाओं की शिक्षा, सम्मान और सुरक्षा के सवाल पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। सामाजिक असमानताएं आज भी कई रूपों में हमारे सामने मौजूद हैं।

ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि बदलाव केवल नारों से नहीं आता बल्कि साहस, संघर्ष और प्रतिबद्धता से आता है। उन्होंने जो मशाल जलायी थी, वह केवल इतिहास की धरोहर नहीं है, बल्कि आज भी सामाजिक परिवर्तन की राह को रोशन करने वाली लौ है।

मेरे प्यारे पापा

पापा की गोदी गर्म-गर्म,
जैसे धूप सुहानी।
बैठा हूँ मैं चिपक के उनसे,
दुनिया लगे कहानी।

छोटी बोतल हाथ में मेरी,
घूंट-घूंट मुझे पिलाते।
पापा हँसकर देख रहे हैं,
मुझ पर प्यार लुटाते।

पापा संग जब खेलूँ मैं,
दिल मेरा खिल जाता।
उनकी गोदी, उनका कंधा,
सबसे प्यारा लगता।

मेरे पापा सबसे अच्छे,
मुझको खूब हँसाते।
छोटा हूँ मैं, बड़ा बनूँगा,
उन जैसा बन जाऊँगा।

पापा की गोदी प्यारी है,
मुझको सबसे न्यारी है।
पापा मेरे सबसे अच्छे हैं,
दुनिया में सबसे सच्चे हैं।

– डॉ. सत्यवान सौरभ

(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)

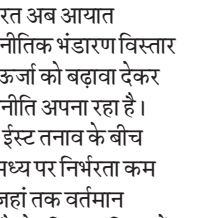

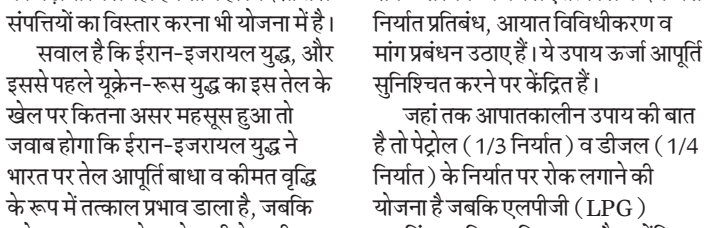

अमृतसर जिले में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के कार्ड बनाने के लिए जिला प्रशासन ने चलाया विशेष अभियान

जिले के गांवों और शहरों में 58 विशेष सुविधा कैंप लगाए गए 544 कॉमन सर्विस सेंटरों के अलावा डिवीजनल और सब-डिवीजनल अस्पतालों में भी बनाए जा रहे हैं कार्ड

अमृतसर, 10 मार्च (साहिल बेरी)

– पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त अमृतसर दलविंदरजीत सिंह ने बताया कि जिले के गांवों और शहरी क्षेत्रों में 58 सुविधा कैंप लगाए गए हैं, जहां लोगों के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिले में 544 कॉमन सर्विस सेंटरों पर भी ये कार्ड बनाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि जिले के सभी डिवीजनल और सब-डिवीजनल अस्पतालों में भी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासनिक परिसर अमृतसर स्थित सेवा केंद्र में भी कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाभार्थी सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ नामी निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज करवा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि जिले के 89 नामी अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जहां लाभार्थी मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का कार्ड बनवाने के लिए परिवार के कम से कम दो सदस्यों का एक साथ जाना जरूरी है। 18 वर्ष से कम आयु के सदस्य को जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, जबकि 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य को वोटर कार्ड और आधार कार्ड साथ लेकर जाना आवश्यक है।

उन्होंने जिले के लोगों से अपील की कि वे इस स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड अवश्य बनवाएं, ताकि जरूरत के समय इसका लाभ मिल सके। उन्होंने इस कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं इसकी निगरानी करें और लोगों को कार्ड बनवाने में किसी प्रकार की परेशानी न आने दें।

पंजाब सरकार ने अपने बजट में अपने सभी चुनावी वादे पूरे किए: जसकरण सिंह बंदेशा

उद्योग-पक्षीय बजट पंजाब को निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनाएगा : बंदेशा

अमृतसर, 10 मार्च (साहिल बेरी)

पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट को उद्योग-पक्षीय और जन-हितैषी बताते हुए पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के वाइस चेयरमैन श्री जसकरण सिंह बंदेशा ने कहा कि मान सरकार ने इस बजट में औद्योगिक क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा है, जिसका उद्देश्य आने वाले समय में इस क्षेत्र के अधिकतम विकास को सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि यह प्रगतिशील बजट पेश करके पंजाब सरकार ने अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह एक जन-पक्षीय बजट है, जिसमें हर वर्ग और क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। यह बजट पंजाब के हर नागरिक को सशक्त बनाते हुए राज्य के आर्थिक विकास को और तेज करेगा।

वाइस चेयरमैन श्री जसकरण सिंह बंदेशा ने कहा कि बजट में औद्योगिक क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है ताकि यह और अधिक तरक्की कर सके और पंजाब निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरे। उन्होंने बताया कि केवल वर्ष 2025 में ही पंजाब को 55,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि यह बजट उद्योगपतियों के हित में है और पंजाब के उद्योग को समृद्धि की ओर ले जाएगा। इसी उद्देश्य से पंजाब सरकार ने नई औद्योगिक नीति भी पेश की है, जो व्यापारियों की सभी जायज मांगों को पूरा करेगी।

उद्योग और जन-हितैषी बजट पेश करने के लिए वाइस चेयरमैन श्री जसकरण सिंह बंदेशा ने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री श्री हरपाल सिंह चीमा का धन्यवाद किया।

खटकुरबहाल खदान में कर्मचारियों ने इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओडिशा

राजगांगपुर/भुवनेश्वर: सुंदरगढ़ जिले में कुटरा के पास शिवा सीमेंट लिमिटेड की खटकुरबहाल खदान में कर्मचारियों ने विमेंस डे मनाया। इस इवेंट को मनोज वर्मा, रितेश चटराज, असित दाश, संतोष जयपुरिया और सौभाग्य मिश्रा ने ऑर्गनाइज़ किया था, जिन्होंने महिलाओं की हिम्मत बढ़ाई और मिठाइयां बांटीं। चित्तरंजन महापात्रा, विकास बारला, मिथुन साहू, स्मृतिरंजन पटनायक और अनंत सामल ने इस शानदार इवेंट की तारीफ़ की और सभी महिला वर्कर्स की हिम्मत बढ़ाई।

राज्यसभा चुनाब केलिए नवीन पटनायक हर दिन MLA को मीटिंग के लिए बुला रहे हैं

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओडिशा

भूबनेश्वर : विपक्ष के नेता नवीन पटनायक हर दिन MLA को मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। मीटिंग में वे सिर्फ़ राज्य विधानसभा के बारे में पूछ रहे हैं। वे सभी MLAs से लगभग एक ही तरह से बात करते सुने जा रहे हैं। उन्होंने विधायकों से कहा कि ऐसी चर्चा है कि BJP समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों के पास बहुत पैसा है। लेकिन वह व्यक्ति कभी किसी को कोई पैसा नहीं देता। क्रॉस वोटिंग करने वालों का भविष्य खराब होगा। इसलिए विधायकों को ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जिससे सामाजिक रूप से बदनामी होकर उनका भविष्य खराब हो। सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार बने CA नवीन ने नवीन के घर आने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही यह खबर मिली, नवीन ने घर का मेन गेट बंद करने का आदेश दे दिया, जिसकी बात अब नवीन अपनी पार्टी के विधायकों से कर रहे हैं। दूसरी ओर, BJD के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग से ज़्यादा अपने लंबे राजनीतिक भविष्य के लिए खुद को पाक-साफ रखना ज़रूरी समझा है। दूसरी ओर, BJD और कांग्रेस के विधायक भी असेंबली लॉबी से लेकर अलग-अलग प्राइवेट होटलों में चाय पिलाकर क्रॉस वोटिंग पर चर्चा कर रहे हैं। विपक्षी विधायकों को भी यह एहसास हो गया है कि क्रॉस वोटिंग आसान नहीं होगी। रूलिंग पार्टी के सपोर्ट वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के यह दिखाने के बाद कि वे 2002 की तरह राज्यसभा चुनाव जीतेंगे, सोशल मीडिया पर इस पर बहुत चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि 2002 में डिजिटल ज़माना नहीं था। तब सीक्रेट बैलेट सिस्टम होने के बावजूद, क्रॉस-वोटिंग करने वालों के बारे में सबको पता था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारत डिजिटल दुनिया में बहुत आगे निकल गया है। इसलिए अगर 2002 के मुकाबले 2026 में कोई MLA क्रॉस-वोटिंग करता है, तो भारत के डिजिटल सिस्टम के ज़रिए उसकी बुराई की जाएगी। इस बात की बहुत चर्चा है कि दुनिया के कोने-कोने में लोगों को बताया जाएगा कि जिन MLAs ने क्रॉस-वोटिंग की है, उन्होंने अपना पैसा बर्बाद किया है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डिप्टी कमिश्नर ने 33 महिला बी.एल.ओ. को किया सम्मानित

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डिप्टी कमिश्नर ने 33 महिला बी .एल .ओ . को किया सम्मानित
कुशल कार्य करने वाली महिला बी .एल .ओ . चुनाव प्रक्रिया का अहम स्तंभ – डिप्टी कमिश्नर
ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने महिला बी .एल .ओ . से की बातचीत

अमृतसर, 10 मार्च (साहिल बेरी)

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अमृतसर श्री दलविंदरजीत सिंह द्वारा जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी ईमानदारी, लगन और समर्पण भावना से निभाने वाली 33 महिला बूथ लेवल अधिकारियों (बी.एल.ओ.) को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्हें चुनाव प्रक्रिया में दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए।

डिप्टी कमिश्नर श्री दलविंदरजीत सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सही और अद्यतन मतदाता सूची का होना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बी.एल.ओ. की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बी.एल.ओ. को चुनाव प्रक्रिया का अहम स्तंभ बताते हुए कहा कि महिला बी.एल.ओ. घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं की पहचान करती हैं तथा नए मतदाताओं का पंजीकरण और आवश्यक संशोधन कर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

डिप्टी कमिश्नर ने महिला बी.एल.ओ. द्वारा निभाई जा रही सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि उनका समर्पित कार्य अन्य कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सम्मानित महिला बी.एल.ओ. से बातचीत भी की और ड्यूटी के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि ड्यूटी निभाते समय किसी प्रकार की समस्या आती है तो जिला प्रशासन द्वारा उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने सम्मानित महिला बी.एल.ओ. को बधाई देते हुए उन्हें भविष्य में भी इसी तरह निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी शिक्षा)-कम-जिला स्वीप नोडल अधिकारी श्री राजेश शर्मा, चुनाव तहसीलदार श्री इंदरजीत सिंह, चुनाव कानूनगो श्री रजिंदर सिंह, स्वीप इंचार्ज सौरव खोसला, श्री राज कुमार और पंकज कुमार भी उपस्थित थे।

कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विभिन्न जिलों से 400 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपे

अमृतसर, 10 मार्च (साहिल बेरी)

जनता के हित में एक और सराहनीय पहल करते हुए कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने नागरिकों के गुम हुए 400 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक ट्रेस कर लिए हैं। ये मोबाइल फोन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पंजाब के विभिन्न जिलों जैसे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर देहाती क्षेत्र से बरामद किए गए और अब इन्हें उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिया गया है।

यह तीसरी बड़ी पहल है जिसके तहत गुम हुए मोबाइल फोन ट्रेस कर नागरिकों को लौटाए गए हैं। इससे पहले पहले चरण में 100 मोबाइल फोन और दूसरे चरण में 200 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए गए थे, जबकि अब तीसरे चरण में 400 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक ट्रेस कर वापस किए गए हैं।

आईपीएस श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर, पुलिस कमिश्नर अमृतसर के निर्देशों पर कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर की टीमों ने तकनीकी प्रयासों के माध्यम से इन मोबाइल फोन को ट्रेस किया। कुल 400 मोबाइल फोन में से 269 मोबाइल फोन पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम टीम द्वारा, 85 सब-डिवीजन ईस्ट द्वारा, 29 सब-डिवीजन सेंट्रल द्वारा और 17 सब-डिवीजन नॉर्थ द्वारा ट्रेस किए गए।

बरामद किए गए मोबाइल फोन में 13 आईफोन और विभिन्न कंपनियों के 387 एंड्रॉयड फोन शामिल हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 85,20,000 रुपये है।

तकनीकी सर्विलांस और दूरसंचार मंत्रालय द्वारा जारी सीईआईआर (Central Equipment Identity Register) सिस्टम की सहायता से जांच के दौरान इन मोबाइल फोन को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विभिन्न जिलों जैसे लुधियाना, जालंधर तथा अमृतसर देहाती क्षेत्र से ट्रेस किया गया, जिसके बाद इन्हें उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया।

पुलिस ने आम जनता को सलाह दी है कि यदि किसी का मोबाइल फोन गुम हो जाए तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या संयुक्त केंद्र में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। साथ ही नागरिकों को दूरसंचार मंत्रालय के सीईआईआर पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे गुम हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रेस करने में मदद मिलती है तथा उनके दुरुपयोग को रोका जा सकता है।

ट्रेस किए गए मोबाइल फोन का विवरण:

पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम: 269

सब-डिवीजन ईस्ट: 85

सब-डिवीजन सेंट्रल: 29

सब-डिवीजन नॉर्थ: 17

कुल: 400 मोबाइल फोन

दम तोड रहा है झारखंड में ढाई हजार साल पुरानी एक शास्त्रीय भाषा - ओड़िया

ओड़िया शास्त्रीय भाषा दिवस पर विशेष
गुरु संदीपनी ने कृष्ण को सिखाई थी ओड़िया, संस्कृत के बाद सर्वाधिक पांडुलिपि धारक प्रभू जगन्नाथ की भाषा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्तम्भ कार -झारखंड

यह सोलह आने सच है जिस भाषा का संबंध भरत मुनि के उस नाट्य शास्त्र मे वर्णित ओड्र विभाषा का जीक्र है वहीं ओडिया भाषा है । जिस नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति तेत्रा युग कह कर उल्लेख है आगे अभिनव गुप्त की रचना -आभिनव भारती में कहा गया है :-

तेन सर्वेसु तेत्रायुगेसु
नाट्य प्रवृत्तित्यं भगवती ।२

इसके अलावे द्वापर में स्वंय कृष्ण का दिल आज भी उत्कल में जगन्नाथ के रुप में विद्यमान है आप ने गुरु संदिपनी के आश्रम में ओड़िया की शिक्षा ग्रहण की थी । यह सारला दास के ओडिया महाभारत में स्पष्ट रूप में वर्णन है ।जिस महाभारत संस्कृत महाभारत से कहीं अपनी मौलिकता के लिये उत्कल भूमि में अपना एक अलग पहचान दिलाये रखा है विश्व भर में।

जिस किसी भारतीय भाषा की सर्वाधिक पांडुलिपियां संस्कृत के बाद भारत वर्ष में विद्यमान है वह- ओड़िआ भाषा है ।पर झारखंड की राजनीती ने इसे ग्रहण लगाकर निगल डाला है । आज स्थिति ऐसी की संविधान भी शर्मा जाए राजनेताओं , दलालों का षड्यंत्रकारी करतूत देखकर झारखंड में ।

इन्हीं सब कारणों से शायद ओडिशा में आई बड़ी तूफान 1999 के बाद कुछ भाषाओं को शास्त्रीय घोषित कराने का मुहिम पकड़ा । पहले संस्कृत के बाद आगे अन्य को मिला शास्त्रीयता का दर्जा । इसी क्रम में 21फरवरी 2014 को देश मेज्ञ छठे शास्त्रीय भाषा का मान्यता मिला इसे, पर सच तो यह है कि प्रथम भारतीय आर्य भाषा भी ओडिया ही रहा है ।कारण संस्कृत को हम छोड़ दें तो बाकी चार द्राविड़ संगठन से आते और वे है तामिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयालम है। पर ओडिया संस्कृत से अलग अपनी मौलिकता का पहचान को लेकर रहा है ।

महामेघ वाहन खारवेल यानी दूसरी सदी के इतिहास को जानते हैं जिन्होंने वैशाली और पाटली पुत्र में पहुंचकर अशोक को ललकारा था उनकी सेना ओड़िया की थी । वह ललकार कलिंग की लड़ाई के बाद थी । लड़ाई के बदले उसने हाथ जोड़ दिए , तब अशोक धर्माशोक बन गया था। उसकी सेनाएं मीट चुकी थी । इसी कलिंग युद्ध मैदान में । तब उत्कल की सीमाएं गंगा से गोदावरी तक बनी । आज का गंगा से गोदावरी तक ओड़िया साम्राज्य हुआ करता था । फिर भौमकर वंश यानी सोमवंशी (केशरी) क्षत्रिय ,जिनमें आज ओडिशा के अधिकांश खड़ायत आते । उत्कल, कोशल, कलिंग यानी आज का समुचा झारखंड प्रदेश त्रि कलिंग बना कर शासन किया था ।उसके बाद हरचंडी जजाती २ ने आधुनिक ओडिशा के ओड़िया अंचल के नींव स्थापित किया ।

अब आइये असली बात पर विगत शदी में उत्कल गौरव मधुसुदन दास ने उन्हीं इलाकों को एकत्रित करने में अंग्रेज के विरूद्ध लडते रहे । । यह सबको पता है पर कितनों को पता जब उनके जन्म दिवस पर आज सरायकेला में ओडिया स्कूल बंद हों । जो महज सौ साल पहले बिहार के राजधानी पटने में मंत्री रहे । बिहार ओडिशा परिषद में ।

बात महज नौ साल पुरानी है । 2018 में सरायकेला मे उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी के जन्मदिन पर 28 अप्रैल को अनेक ओड़िया स्कुलों को बंद कर हिन्दी स्कूलों मे विलय कर दी गयी थी । तब वह तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने यह सब किया था जहां सरायकेला का मार्जार एग्रीमेंट एवं सिंहभूम में गोपबंधू गोदावरीश के की ओड़िया बचाने की मुहिम को दफन कर यह सब कुछ की गयी । जिसको लेकर मेरा सांकेतिक हड़ताल था अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला के संदीप दुवे सामने । तब एस डी ओ सरायकेला ने काफी अफसोस जताते हुए खबर राज्य सरकार को भेजी थी , नतीजा डाक के तीन पात ।

झारखंड के सरायकेला , खरसावां, सिंहभूम में आज तक कोरा साबित होता आ रहा भारतीय संविधान में लिखा वह अधिकार जहां स्पष्ट लिखा है -मातृभाषा में शिक्षा पाना सबका अधिकार है देश में ।विरोध ऐसा रहा कि मेरे अनशन को समर्थन करते घंटों अपने स्कूल में प्रतिदिन अनशन पर बैठे रहे बच्चे , उस धोबी साही स्कूल में । जबरन उन्हें रानी पद्मिनी में भेजा गया ।

यह वह स्कूल रहा जहां मेरे पिता स्व स्वर्गीय मनसुख लाल परिच्छा एवं उनके सहपाठी रहे स्व मिश्रीलाल चौधरी (सेवानिवृत्ति जिला सत्र न्यायाधीश) का विधालय था कभी । तब सभी ओडिया पढ़ते थे चाहे वे मारवाड़ी हों या महंतों - आदिवासी ।

ओड़िया भाषाई स्कूल होते हुए भी उसे बंद करवा दिया जाय महान हस्ती मधुसूदन दास के जन्म दिवस पर जिस दिन को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है भला कभी ऐसा कभी हुआ है न होगा । इतना ही नहीं स्कूल स्थापना वर्ष 1957दर्ज है दीवार पर क्या मेरे पिता जी एवं उक्त जिला सत्र न्यायाधीश उसी वर्ष पढ़ें या काफी पहले 1940-45 में पढ़ें थे वहां ? धन्य बिहार सरकार फिर झारखंड में सरकार ।

केवल एक नहीं अनेक स्कूल है सरायकेला में जहां ओडिया भाषा रही 1990 -2000तक ,पर आते आते बंद कर दिये गये उस शास्त्रीय भाषा को जिसका राजनीति उद्देश्य पर देखा जाय तो एक षड्यंत्र की बू आती है ।पर कहां तक उचित एक शास्त्रीय भाषा की यूं हत्या किया जाना ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023